सांध्य दैनिक

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534

डाक पंजीयन क्र.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 320 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, गुरुवार 03 सितंबर 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

हर खंबे पर अवैध बैनर-पोस्टर, लाचार निगम ने खड़े किए हाथ

- प्रति माह हो रहा राजस्व का नुकसान
- पंजीकृत एडवर्टाइजर्स के साथ नाइंसाफी
- जोन-1 में निगम कार्यालय के सामने भी भरमार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर निगम क्षेत्र के चप्पे-चप्पे पर स्कूल, कालेज, अस्पताल, क्लिनिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों के बैनर पोस्टर लगे हैं। इनमें से 90 फीसद से ज्यादा अवैध हैं जिनके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है। इससे न केवल नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि पंजीकृत एडर्वाइजर्स को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिजली के खंबों पर लगे ये पोस्टर बैनर लटकते-गिरते रहते हैं जिसके कारण यातायात की सुरक्षा भी खतरे में आ जाती है।

शहर के पंजीकृत एडर्वाइजर्स के अनुसार अवैध बैनर-पोस्टरों और विज्ञापन बोर्डों का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों से लेकर विभिन्न मुख्य मार्गों पर बिजली के खंभों तक बड़ी संख्या में बैनर-पोस्टर और विज्ञापन बोर्ड लगाए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि भिलाई नगर निगम के जोन-1 कार्यालय के सामने भी सैकड़ों विज्ञापन बोर्ड और पोस्टर नजर आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। स्थानीय लोगों और विज्ञापन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि शहर में सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाने का सिलसिला लंबे समय से जारी है। इस संबंध में कई बार नगर निगम का ध्यान भी आकर्षित कराया गया, बावजूद इसके स्थिति में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया।

जवाबदेही तय करने की मांग

नागरिकों और नियमों का पालन कर विज्ञापन लगाने वाले कारोबारियों ने नगर निगम प्रशासन से शहरभर में लगे विज्ञापन बोर्ड और बैनर-पोस्टरों का सर्वे कराने, अवैध विज्ञापनों की पहचान कर उन्हें तत्काल हटाने तथा जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना होगा कि नगर निगम प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करता है या फिर अवैध विज्ञापन का यह सिलसिला यूं ही शहर की सड़कों और बिजली के खंभों पर चलता रहेगा।

कार्रवाई क्यों नहीं? उठ रहे सवाल

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब निगम कार्यालय के सामने ही बड़ी संख्या में विज्ञापन बोर्ड और पोस्टर लगे हुए हैं, तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इन पर नहीं पड़ती? यदि ये विज्ञापन अधिकृत हैं तो निगम को इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए और यदि इनमें से बड़ी संख्या में विज्ञापन बिना अनुमति लगाए गए हैं, तो अब तक इन्हें हटाने और संबंधित लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? शहर में लगातार बढ़ रहे अवैध विज्ञापनों को लेकर अब यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर इन विज्ञापनदाताओं पर कार्रवाई करने में नगर निगम प्रशासन इतनी नरमी क्यों बरत रहा है?

नियमों का पालन करने वालों को नुकसान

एक ओर नगर निगम द्वारा अधिकृत स्थानों पर विज्ञापन लगाने वाले कारोबारियों और एजेंसियों से निर्धारित शुल्क एवं टैक्स लिया जाता है, वहीं दूसरी ओर यदि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन लगाए जा रहे हैं तो इससे नियमों का पालन करने वाले विज्ञापनदाताओं के कारोबार पर सीधा असर पड़ता है। नियमों के तहत शुल्क जमा कर विज्ञापन लगाने वाले कारोबारियों का कहना है कि जब अवैध विज्ञापनों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी तो नियमों के मुताबिक शुल्क देने वालों के साथ प्रतिस्पर्धा में असमानता की स्थिति जारी रहेगी।

खास-खबर

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया 25 साल पुराना हत्या का मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हुए हत्या के एक मामले में हैरान करने वाला फैसला सुनाया है। इस मामले में जिन 6 लोगों को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले को ही खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में कोई जांच ही नहीं हुई। सबसे हैरानी की बात यह है कि बिहार पुलिस ने ट्रायल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में सभी 6 लोगों के खिलाफ अपना केस साबित कर दिया था। ये मामला साल 2001 में दिन-दहाड़े एक शख्स की हत्या करने के लिए अंधाधुंध गोलीबारी से जुड़ा है। ट्रायल कोर्ट ने साल 2015 में सजा सुनाई थी, जिसे पटना हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। इसमें 5 दोषियों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। जस्टिस जे बी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि इस मामले में सबूतों की पूरी तरह कमी है, और (प्रत्यक्षदर्शियों के) बयान भरोसे के लायक नहीं हैं।

फ्लाइट में सुलगाई सिगरेट मच गया हड़कंप

लखनऊ। अबूधाबी से लखनऊ आ रहे इंडिगो विमान में एक यात्री ने अपनी सीट पर बैठे-बैठे ही सिगरेट जला ली। विमान के केबिन में अचानक धुआं उठता देख महिला क्रू मेंबर की नजर उस पर पड़ी। इसके बाद सिगरेट तुरंत बुझवाई गई। विमान के अमौसी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने यात्री को हिरासत में ले लिया और बाद में स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। आजमगढ़ में सिरवान गांव का रहने वाला अब्दुल अजीज अबूधाबी में मजदूरी करता है। वह मंगलवार रात 1:25 बजे अबूधाबी से लखनऊ आने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6E-1416 में सवार हुआ था।

योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित तीन अध्यक्षों को मिला राज्यमंत्री का दर्जा

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के विभिन्न निगम, मंडल और आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इस संबंध में शासन ने 2 सितंबर को आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। अजय शुक्ला को छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। वहीं शरद अवस्थी को इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।

शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार (प्रोटोकॉल) के लिए प्रदान किया गया है। संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासनिक विभाग/आयोग का होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि यह सूची किसी प्रकार की वरिष्ठता या प्रोटोकॉल की स्थिति नहीं दर्शाती है। राज्य मंत्री का दर्जा आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावशील होगा।

भारत करेगा महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी आईसीसी ने वेन्यू और तारीख का किया एलान

- टूर्नामेंट का आयोजन 14 से 28 फरवरी 2027 तक

नईदिल्ली ए.। आईसीसी ने पहले महिला चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू और तारीख का एलान कर दिया है। आईसीसी ने बताया कि छह टीमों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन 14 से 28 फरवरी 2027 तक भारत में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और वडोदरा के वडोदरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

आईसीसी ने बताया कि ये टूर्नामेंट पहले श्रीलंका में आयोजित होना था, लेकिन अब इसे भारत में शिफ्ट किया गया है। श्रीलंका क्रिकेट के प्रशासन में सरकारी

हस्तक्षेप के कारण इसे श्रीलंका से बाहर स्थानांतरित किया गया है। आईसीसी ने टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए तीन दावेदारों बांग्लादेश, भारत और दक्षिण अफ्रीका का उनके तय मेजबान मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर आकलन किया और फिर भारत को वैकल्पिक मेजबान के तौर पर चुनने की सिफारिश की। इस फैसले को एक सितंबर को आईसीसी बोर्ड ने मंजूरी दी।

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा, आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 महिला क्रिकेट के लिए एक रोमांचक नए अध्याय की शुरुआत है। टूर्नामेंट के पहले संस्करण के तौर पर यह दुनिया की बेहतरीन टीमों को एक कड़े और हाई-क्वालिटी मुकाबले में एक साथ लाएगा। साथ ही यह टीमों को रैंकिंग में ऊपर चढ़ने और वैश्विक स्तर पर जगह बनाने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित करेगा। अब जब आईसीसी का कोई बड़ा महिला टूर्नामेंट हर साल हो रहा है, तो हमारे पास महिला क्रिकेट, इसकी खिलाड़ियों और दुनिया भर में इसके फैंस के लिए बेहतर गति बनाने, ज्यादा निरंतरता लाने और एक मजबूत लय तैयार करने का एक बड़ा मौका है।

भारी बारिश से उफान पर नदियां, गंगरेल बांध के खुले 3 गेट, अलर्ट जारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। धमतरी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है, वहीं क्षेत्र के सभी प्रमुख जलाशय अब पूरी तरह लबालब हो चुके हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगरेल बांध (रविशंकर सागर जलाशय) के तीन गेट खोल दिए गए हैं, जिनसे कुल 4,670 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसमें से 3,360 क्यूसेक पानी सीधे महानदी में बह रहा है, जबकि 1,410 क्यूसेक पानी रुद्री बैराज के रास्ते मुख्य नहर में प्रवाहित किया जा रहा है।

मौसम विभाग द्वारा आगे भी बारिश की संभावना जताए जाने से महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका है, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने तटीय और निचले इलाकों में स्थित गांवों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वर्तमान में जिले के जलाशयों की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है।

बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान को मिली सफलता, जंगल से मिला हथियार और गोला-बारूद

श्रीकंचनपथ न्यूज

बीजापुर। नक्सल विरोधी एवं सुरक्षा अभियान के तहत बीजापुर पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस ने भोपालपटनम थाना क्षेत्र के ग्राम नीलमडगु के जंगल में नदी किनारे छिपाकर रखा हथियार और गोला-बारूद का डंप बरामद किया है। बरामद सामग्री को विधिवत जब्त कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, एक सितंबर 2026 को भोपालपटनम थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम नीलमडगु के जंगल में नदी किनारे कुछ संदिग्ध सामग्री छिपाकर रखी गई है। सूचना की तस्दीक और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए संयुक्त सुरक्षा दल को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। सर्चिंग के दौरान जवानों को नदी किनारे कटे हुए पेड़ के खोखले हिस्से में लावारिस हालत में छिपाकर रखा गया हथियार और गोला-बारूद का डंप मिला। तलाशी के दौरान मौके से 12 बोर का एक देशी

कट्टा, एक टूटी हुई भरमारराइफल, 8 भरमारसेल, 12 बोर के देशी कट्टे के 10 जिंदा राउंड, 3 देशी कट्टा सेल कैप, एक पेचकस और एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नक्सल विरोधी अभियान के तहत जंगलों और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग एवं निगरानी की जा रही है। यह संयुक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बीजापुर उमेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में की गई। अभियान में एसडीओपी भोपालपटनम घनश्याम कामड़े, थाना प्रभारी भोपालपटनम मुकेश पटेल, डीआरजी बीजापुर, बीडीएस टीम और थाना भोपालपटनम के जवानों की भूमिका रही।

रैट माइनर्स ने की नेपाल में मदद की पेशकश

नई दिल्ली। नेपाल में बाढ़ के बाद हाइड्रोपावर परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए 'रैट माइनर्स' की टीम ने मदद की पेशकश की है। यह वही टीम है, जिसने 2023 के सिल्क्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। टीम ने नेपाल में राहत और बचाव अभियान में शामिल होने की इच्छा जताई है। बाढ़ से नेपाल के रसुवा और नुवाकोट जिलों में कम से कम 12 हाइड्रोपावर परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। इनमें चार निर्माणाधीन, सात चालू और एक परीक्षण चरण में थी। सुरंगों के कई हिस्से बंद या ध्वस्त हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 900 मजदूर लापता हैं, जबकि लगभग 500 लोगों के सुरंगों के अंदर होने की आशंका है।

जशपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर ने मांगे रुपए, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत, कलेक्टर ने बनाई जांच टीम

श्रीकंचनपथ न्यूज

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला अस्पताल के एक डॉक्टर पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आरोप है कि प्रमाण पत्र बनाने के बदले उन्होंने 500 रुपए लिए। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने सर्टिफिकेट बनाने के लिए 1 हजार रुपए मांगे थे। मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

इस वायरल वीडियो में डॉक्टर पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन के जरिए की गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर रोहित व्यास ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक जांच टीम बनाई

है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक फिलहाल मामले की जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ होगी।

मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए पहुंचे थे अस्पताल

जानकारी के मुताबिक, सन्ना थाना क्षेत्र के कवई गांव निवासी मुक्तेश्वर राम 4 जुलाई 2026 को वह अपने दोस्त सहिन्द्र राम की बेटी करिश्मा का मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए राजा देवशरण जिला अस्पताल पहुंचे थे। मुक्तेश्वर के अनुसार, करिश्मा को आरा चौकी क्षेत्र के झपरा में बने पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में एडमिशन लेना था। छात्रावास में एडमिशन के लिए करिश्मा का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जिला अस्पताल गए थे। जिला अस्पताल में उनकी मुलाकात डॉ. धीरेन्द्र अग्रवाल से हुई। उन्होंने डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने कहा। डॉक्टर ने इसके बदले 1 हजार रुपए की मांग की। मुक्तेश्वर ने बताया कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने डॉक्टर से कम पैसे लेने की गुजारिश की। इसके बाद कथित तौर पर डॉक्टर 500 रुपए में मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने के लिए तैयार हो गए।

पाकिस्तान का फाइटर जेट गिराने वाले अभिनंदन अब एयरलाइन फ्लाई 91 के साथ भरेंगे उड़ान

नईदिल्ली। भारतीय वायुसेना के पूर्व ग्रुप कैप्टन और वीर चक्र से सम्मानित अभिनंदन वर्धमान ने अब विमानन क्षेत्र में नई पारी शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने गोवा स्थित क्षेत्रीय एयरलाइन FLY 91 में पायलट के तौर पर ज्वाइन किया है। सूत्रों ने बताया कि अभिनंदन अगस्त में एयरलाइन से जुड़े। हालांकि, एफएलवाई 91 के प्रवक्ता ने कर्मचारियों की निजी जानकारी का हवाला देते हुए इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

अभिनंदन वर्धमान 2019 में भारत-पाकिस्तान के बीच हवाई संघर्ष के दौरान दुश्मन के एक विमान को मार गिराने के बाद

चर्चा में आए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान में तीन दिन तक हिरासत में रखा गया था। हवाई मुकाबले के दौरान असाधारण कर्तव्यनिष्ठा दिखाने के लिए उन्हें 2021 में वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वीर चक्र भारत के तीसरे सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों में शामिल है। पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र में उनके कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण और साहस की सराहना की गई थी।

जानिए फ्लाई 91 के पास कितने विमान

गोवा स्थित एफएलवाई91 ने मार्च 2024 में अपनी उड़ान सेवाएं शुरू की थीं। एयरलाइन के पास फिलहाल छह ATR 72-600 विमान हैं। कंपनी के दो प्रमुख बेस गोवा और हैदराबाद में हैं। अभिनंदन के FLY91 से जुड़ने की खबर ऐसे समय सामने आई है, जब भारतीय विमानन क्षेत्र में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है।

वायुसेना ने 26-27 फरवरी 2019 की रात पाकिस्तान के बालाकोट में एयरस्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के जेट विमान को मार गिराया था।

संपादकीय

एसआईआर के सवाल

बूथ-स्तरीय अधिकारियों पर तनाव का असर

निस्संदेह, किसी लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष होनी चाहिए। साथ ही मतदाताओं की विश्वसनीयता भी उतनी जरूरी है ताकि वाजिब वोट ही चुनाव प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाए। इसी आलोक में नौ राज्यों व तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल तार्किक समाधान मांगते हैं। इस प्रक्रिया में तुरत-फुरत की कार्यनीति के चलते कई राज्यों में अफरा-तफरी का आलम नजर आता है। जिसका दबाव जमीनी स्तर पर इस प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर पड़ रहा है। कई बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ बेहद तनाव में नजर आ रहे हैं। इनका कार्य मतदाता सूचियों को अपडेट करना है। पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में कम समय में अधिक काम के दबाव के चलते कुछ बीएलओ के मरने व आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं। आरोप है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों द्वारा भी उन्हें परेशान किए जाने का आरोप है। हालांकि, इस अव्यवस्था के चलते ही चुनाव आयोग ने अब एसआईआर के कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। लेकिन कहना कठिन है कि इस कदम से बीएलओ का तनाव कम करने या विभिन्न हितधारकों की आशंकाओं को दूर करने में कोई खास मदद मिल सकेगी। कहा जा रहा है कि एक माह पहले शुरू हुई राष्ट्रव्यापी एसआईआर प्रक्रिया में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। इस प्रक्रिया में करीब 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं, जो तकरीबन भारतीय आबादी का एक-तिहाई से भी ज्यादा। उनकी शिनाख्त से जुड़ी जानकारी को एक निश्चित समय सीमा में प्रमाणित कर पाना आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि निर्धारित समय-सीमा व्यावहारिक नहीं है। तीन महीने की अवधि में गणना प्रपत्रों का वितरण, उसके बाद मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन और फिर अंतिम मतदाता सूची जारी करना आसान काम नहीं है। बहुत तेजी से काम को अंजाम देने का जिम्मा अधिकारियों पर अतिरिक्त दबाव बना रहा है।

> “ कई बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ बेहद तनाव में नजर आ रहे हैं। इनका कार्य मतदाता सूचियों को अपडेट करना है। पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में कम समय में अधिक काम के दबाव के चलते कुछ बीएलओ के मरने व आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं। आरोप है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों द्वारा भी उन्हें परेशान किए जाने का आरोप है।

निस्संदेह, स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का शुद्धीकरण एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन महत्वपूर्ण काम को जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। मतदाता को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय मिले ताकि उनके नाम सूचियों में सही ढंग से दर्ज हो सकें। यही बात बीएलओ के लिए भी लागू होती है, ताकि वे अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहराव वाले मतदाताओं का डेटा संकलित करने के लिए बूथ-स्तरीय एजेंटों के साथ मिलकर सुचारु रूप से काम कर सकें। यदि एसआईआर की प्रक्रिया किसी विवाद में उलझी रहती है तो इस अभियान का उद्देश्य ही विफल हो सकता है। बिहार की एसआईआर प्रक्रिया के घटनाक्रमों से मिले सबक को अन्य राज्यों में इस प्रक्रिया के दौरान याद रखा जाना चाहिए। निस्संदेह, स्तरहीन व संदिग्ध एसआईआर हमारे चुनावी लोकतंत्र की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचा सकता है। उल्लेखनीय है कि विशेष गहन पुनरीक्षण की यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों तथा अंडमान-निकोबार, लक्ष्यद्वीप व पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेशों में जारी है। उल्लेखनीय है कि जहां बीएलओ पर कार्यदबाव व समय सीमा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं कई राज्यों में बीएलओ के खिलाफ मामले दर्ज करने के भी आरोप लगे हैं। इन अधिकारियों का आरोप है कि अतिरिक्त कार्य-दबाव का उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। वहीं चुनाव आयोग का आरोप है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते प्रक्रिया की निष्पक्षता व पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। वैसे यदि वास्तव में बीएलओ पर अतिरिक्त दबाव है तो चुनाव आयोग को इस मुद्दे का समाधान संवेदनशील ढंग से करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मतदाता पहचान से जुड़े प्रमाणपत्रों को जुटाने में आ रही परेशानियों के चलते लोग भी बीएलओ पर दबाव बनाते हैं। कई राज्यों में बीएलओ संगठनों ने प्रदर्शन करके अधिक समय दिए जाने की मांग भी की है। कुछ लोग चुनाव आयोग की जल्दबाजी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वे समय पर दायित्व न निभा पाने वाले बीएलओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अनुचित बताते हैं।

सिंधु जल विवाद केस जीतकर भी दुखी पाक

पुष्परंजन

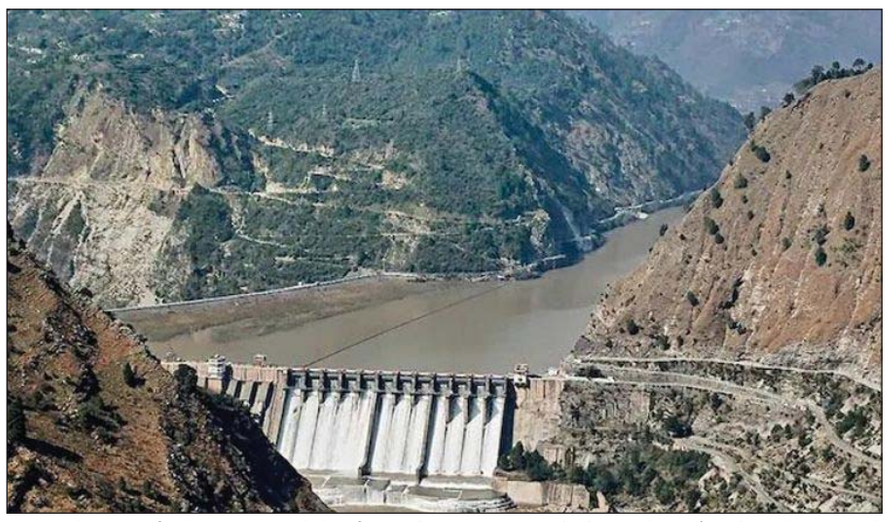

सवाल है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यदि पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुना भी दिया, तो उसे लागू कैसे करवाएगा? भारत ने कुछ ही घंटों में इस फैसले को खारिज कर दिया था।

नीदरलैंड के हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा सिंधु जल विवाद के एकतरफा फैसले पर पाकिस्तान बल्ले-बल्ले, शाबाश-शाबाश करने लगा है। हेग स्थित 'पीसीए' ने सोमवार को फैसला सुनाया है कि भारत एकतरफा तरीके से सिंधु जल संधि को सस्पेंड नहीं कर सकता। कोर्ट ने नई दिल्ली की उन सभी दलीलों को खारिज कर दिया है, जिनका इस्तेमाल उसने छह दशक पुराने जल-बंटवारे के समझौते को अप्रैल, 2025 से 'स्थगित' रखने को सही ठहराने के लिए किया था।

सोमवार को सुनाए गए सर्वसम्मत फैसले में पांच सदस्यीय कोर्ट ने पाया कि संधि 'पूरी तरह से लागू है' और भारत को इसके तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। इसमें पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों पर पनबिजली परियोजनाओं के डिजाइन और संचालन से जुड़ी जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। पहलगाम हमला 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के बैसारन घास के मैदानों में हुआ था, जिसमें पाक-पोषित बंदूकधारियों ने बर्बरता से 26 लोगों की जान ले ली थी। बंदूकधारियों ने गोली दागने से पहले उनसे उनका धर्म पूछा था। इस नरसंहार के बाद, भारत ने कहा था कि वह संधि को तब तक सस्पेंड रखेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद को 'विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय' रूप से खत्म नहीं कर देता।

इस्लामाबाद इन आरोपों से इनकार करता है कि वह हमले के पीछे था। लेकिन माजी में दी उसकी धमकियों से कोई मानने को तैयार नहीं कि पहलगाम कांड में उसका हाथ नहीं रहा है। बहरहाल, पाकिस्तान द्वारा हेग में लाए गए सिंधु जल संधि मामले में भारत ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (पीसीए) के अधिकार क्षेत्र को मानने से इनकार कर दिया है।

पाकिस्तान में जलविद्युत परियोजनाएं बनवाने वाला चीन इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। माजी में चीन ने भी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के एक ऐतिहासिक फैसले को खारिज कर दिया था, जो दक्षिण चीन सागर के विवाद पर फिलीपींस के पक्ष में आया था। ऐसा नहीं कि नीदरलैंड के हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में भारत ने कोई केस लड़ा ही नहीं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत अब तक 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मामलों का हिस्सा रहा है।

मगर सवाल है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यदि पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुना भी दिया, तो उसे लागू कैसे करवाएगा? भारत ने कुछ ही घंटों में इस फैसले को खारिज कर दिया था। यह दिलचस्प है कि 1 सितंबर, 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक ही मंच पर मौजूद रहे, लेकिन दोनों में न बात हुई, न इस विषय पर कोई चर्चा।

हालांकि, इस्लामाबाद में रहने वाले हाइड्रोलॉजी और जल संसाधन विशेषज्ञ हसन अब्बास इस बात से सहमत नहीं थे कि समझौते के टूटने से फिलहाल पाकिस्तान के लिए कोई तत्काल खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बड़ा खतरा है। पश्चिमी नदियां भौगोलिक स्थिति की वजह से सुरक्षित हैं, न कि मुख्य रूप से संधि की वजह से।'

हसन अब्बास ने बताया कि चिनाब नदी पर भारत की स्टोरेज क्षमता लगभग 1 मिलियन एकड़-फीट (405,000 हेक्टेयर-फीट) है, जो पाकिस्तान की मौसमी सिंचाई की जरूरतों के मुकाबले बहुत कम है। उन्होंने कहा, 'अगर वे कहते हैं कि वे पानी नहीं बहने देंगे, तो वे खुद ही बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि भारत के बांध रन-ऑफ-रिवर हाइड्रोपावर प्लांट हैं, जिनमें पानी जमा करने की जगह बहुत कम होती है।' अब्बास ने कहा, 'एक बार जब उनके बांध भर जाते हैं, तो उनके पास पानी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता।' लेकिन हाइड्रोलॉजी और जल संसाधन विशेषज्ञ हसन अब्बास ने पाकिस्तान के अपने जल प्रबंधन की भी आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि इस्लामाबाद का नए बड़े बांधों पर जोर देना सस्ते समाधानों को नजरअंदाज करता है। जल विशेषज्ञ अब्बास ने कहा कि सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर नए जलाशयों की तुलना में कहीं ज्यादा पानी बचाया जा सकता है।

पाकिस्तान में सिंधु नदी की मुख्य धारा पर वर्तमान में कई प्रमुख मेगा जलविद्युत और बांध परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें दासू और दियामेर-भाशा जैसी बड़ी परियोजनाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। दासू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सिंधु नदी पर बन रहा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके 2027 तक चालू होने की उम्मीद है। उसी तरह दियामेर-भाशा बांध गिलगित-बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सीमा पर सिंधु नदी पर रोलर-कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से बन रहा 272 मीटर ऊंचा विशाल बांध है। इसके अलावा सिंधु नदी बेसिन और उसकी सहायक नदियों पर अन्य छोटी-बड़ी जलविद्युत एवं सिंचाई परियोजनाएं भी निर्माणाधीन हैं। पाकिस्तान के पास पानी का टोटा है, लेकिन जलविद्युत परियोजनाएं मालूम नहीं किसके भरोसे पूरी की जा रही हैं?

सिंधु जल संधि से हटने के भारत के एकतरफा फैसले के बाद से पाकिस्तानी अधिकारियों और मिलिट्री लीडरशिप ने इस विवाद को अस्तित्व के लिए खतरे के तौर पर बताना शुरू कर दिया है। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी बोल चुके हैं कि यह विवाद कोई तकनीकी विवाद नहीं है... यह कागजी कार्रवाई, हाइड्रोलॉजी या प्रशासनिक देरी का मामला भी नहीं है। यह 'पानी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल' है।

बात पाकिस्तान वालों को देर से समझ में आई कि भारत ने उसके विरुद्ध अबूझ 'वाटर बम' का इस्तेमाल किया है। 'इब्तदा-ए-इश्क है, रोता है क्या/ आगे-आगे देखिए, होता है क्या।' लद्दाख से ऐसी खबर आई है, जिसका यदि पालन हो गया, तो पाकिस्तान वाकई बूंद-बूंद पानी के लिए तरसेगा। लद्दाख प्रशासन ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, सिंधु नदी के सीने पर एक साथ 36 डैम्स का जाल बिछाने का। वो पानी, जो अब तक खैरात में सरहद पार जा रहा था। वह पानी अब भारत की बंजर जमीन को सोना बनाने वाला है।

मात्र 56 करोड़ के बजट में लद्दाख ने वो दांव खेल दिया है, जो पाकिस्तान के रणनीतिकारों ने सोचा भी नहीं था। जो प्रस्ताव लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने जल शक्ति मंत्रालय को भेजा है, वह पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ाने वाला कदम है। पहला प्लान है लेह में सात रॉक डैम्स। यह बनेंगे इंडस रिवर के ऊपर। दूसरा प्लान है, कारगिल में 29 आरसीसी डैम्स। यह बनेंगे सुरू नदी पर, जो सिंधु की सबसे ताकतवर ट्रिब्यूटरीज में से एक है। दिल्ली, कब और कितनी जल्दी इस प्रोजेक्ट प्रपोजल को स्वीकार और साकार करता है, उसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन, नई दिल्ली को इसमें देर नहीं करनी चाहिए।

लेखक जियोपॉलिटिकल मामलों के पत्रकार हैं।

मौलिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में न्यायिक पहल

डॉ. जगदीप सिंह

सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी एफआईआर रद्द कर दी। निर्णय अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण विरोध के हक और लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षण व मजबूती देने वाला है। इस निर्णय का मकसद है कि सही मंशा वाले प्रदर्शनकारी युवाओं का भविष्य प्रभावित नहीं हो।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, जो पूरे देश के युवाओं के लिए राहतकारी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुच्छेद 142 की असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जंतर-मंतर और देशभर में हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी एफआईआर को रद्द कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि सद्भावना से आए युवाओं का भविष्य आपराधिक मामलों की छाया में नहीं रहना चाहिए। यह निर्णय सिर्फ कानूनी राहत नहीं। यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और छात्रों के अधिकारों की पुष्टि है।

ये प्रदर्शन नीट-यूजी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी, पारदर्शिता की कमी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुए थे। दिल्ली पुलिस ने अकेले इस अवधि में 13 एफआईआर दर्ज की थीं। हजारों छात्र देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आए और जंतर-मंतर पर जमा हुए। प्रदर्शन जल्द ही कई राज्यों में फैल गया। केंद्र सरकार के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा असम आदि की सरकारों ने अदालत में अर्जी दायर कर इन मामलों को रद्द करने की अनुमति मांगी। अदालत ने न सिर्फ इन अर्जियों को स्वीकार किया, बल्कि पूरे देश पर अपना आदेश लागू कर दिया। किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में उसी घटना से जुड़ी एफआईआर अगर अभी तक सामने नहीं आई, तो उसे भी बंद माना जाएगा। कोई नई एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा सकेगी। ये निर्देश पूरे भारत पर लागू होते हैं। इससे साफ होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी एक शहर या घटना तक सीमित नहीं, यह पूरे देश के नागरिकों का अधिकार है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) हर नागरिक को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। इसमें शांतिपूर्ण सभा और विरोध का अधिकार भी शामिल है। जंतर-मंतर पर छात्र इसलिए इकट्ठा हुए थे, क्योंकि वे परीक्षा व्यवस्था की खामियों और अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर आवाज उठाना चाहते थे। प्रदर्शन लोकतंत्र का स्वस्थ लक्षण है। जब प्रशासन इस आवाज को दबाने के लिए एफआईआर का सहारा लेता है, तो संविधान का मूल उद्देश्य कमजोर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक यही कमजोरी दूर की। अदालत ने कहा कि युवा प्रदर्शनकारी, जो सद्भावना से आए थे, उनके खिलाफ मामले आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं होता। लोकतंत्र में नागरिकों को बिना भय के अपनी बात कहने, नीतियों पर सवाल उठाने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताने का अधिकार होना चाहिए। अगर उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर दिए जाएं, तो युवा पीढ़ी चुप हो जाएगी।

निस्संदेह, अनु.-19 की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। संविधान स्वयं अनुच्छेद-19(2) में उचित प्रतिबंधों का प्रावधान करता है। हिंसा, तोड़फोड़ या गंभीर अपराध करने वालों को राहत नहीं मिलनी चाहिए। अदालत ने ठीक यही संतुलन बनाया। दिल्ली पुलिस को उन लगभग 2,873 व्यक्तियों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी गई, जिनके गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड हैं।

हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे मामलों वाले लोग इस राहत के दायरे से बाहर हैं। यह फैसला दिखाता है कि अदालत स्वतंत्रता और व्यवस्था दोनों की रक्षा कर रही है। शांतिपूर्ण आवाज को जगह दी गई, लेकिन अपराध को बर्दाश्त नहीं किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश विशिष्ट परिस्थितियों में दिया गया है और मिसाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है। परीक्षा प्रणाली, रोजगार और शिक्षा की गुणवत्ता उनके जीवन को तय करती है। जब वे इन मुद्दों पर बोलते हैं, तो उन्हें आपराधिक रंग में रंगना गलत है। एफआईआर का बोझ उनके कैरियर, मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। कई छात्र नौकरी, उच्च शिक्षा या विदेश जाने की तैयारी में होते हैं। आपराधिक केस उनके सपनों पर पानी फेर सकता है।

अदालत ने केंद्र सरकार के उन आश्वासनों को भी नोट किया, जिसमें मुआवजे और मामलों को आगे न बढ़ाने की बात कही गई थी। नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को तीन महीने के अंदर मुआवजा देने का आश्वासन भी रिकॉर्ड किया गया। इससे साफ है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज मिलकर लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं।

यह निर्णय भारतीय न्यायपालिका की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है, जिसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार इसलिए जरूरी है कि सत्ता हमेशा सही नहीं होती। परीक्षा व्यवस्था में खामियां, पेपर लीक होना या पारदर्शिता की कमी-ये मुद्दे सिर्फ छात्रों के नहीं, पूरे समाज के हैं। जब छात्र इन मुद्दों को उठाते हैं, तो समाज में चेतना जगाते हैं।

यह फैसला लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक है। अब कोई भी प्रशासन शांतिपूर्ण प्रदर्शन को आसानी से आपराधिक रंग नहीं दे सकेगा। युवाओं में विश्वास बढ़ेगा कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी। छात्रों पर अंधाधुंध एफआईआर का रास्ता बंद हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने उस आवाज को कानूनी संरक्षण दिया है। अनुच्छेद-19 अब सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि सड़कों पर भी जिंदा है। युवा पीढ़ी को यह संदेश मिला है कि संविधान उनके साथ है। लोकतंत्र उनके साथ है। और न्याय उनके पक्ष में है।

लेखक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।

सकल घरेलू उत्पाद में भारत का प्रभावशाली प्रदर्शन

भारत की अर्थव्यवस्था की शुरुआत 2026-27 के लिए मजबूती के साथ हुई जिसमें विनिर्माण और सेवाओं के अच्छे प्रदर्शन के साथ पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 7.8 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि वास्तविक सकल मूल्य वृद्धि में 8.2 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। निवेश 11.9प्रतिशत तक बढ़ गया; घरेलू खपत 7.1 प्रतिशत बढ़ गई और निर्यात 12.0 प्रतिशत बढ़ गया। यह गति जुलाई में भी जारी रही। औद्योगिक उत्पादन में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अप्रैल-जुलाई के दौरान संचयी व्यापारिक और सेवाओं के निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष 13.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जुलाई में उद्योग और सेवाओं के लिए ऋण क्रमश: 20.0 प्रतिशत और 22.9 प्रतिशत बढ़ा।

भारत की समग्र आर्थिक स्थिति

भारत ने लगातार भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार को लेकर अनिश्चितता के बीच 2026-27 में प्रवेश किया। इन बाहरी दबावों के बावजूद 2026-27 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8 प्रतिशत बढ़ी। यह परिणाम 2023-24 से 2026-27 तक चार वर्षों की अवधि के दौरान पहली तिमाही में दर्ज वास्तविक जीडीपी की उच्चतम वृद्धि को रेखांकित करता है। घरेलू मांग में तेजी तथा विनिर्माण और सेवाओं में लाभ से इसे समर्थन मिला है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका का उल्लेख किया है। जुलाई 2026 में इसने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक और वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन बताया।

भारत की ऋण संबंधी साख के मूल्यांकन में भी इसकी झलक मिलती है कि विश्व को भारत की अर्थव्यवस्था पर पूरा भरोसा है। अगस्त 2026 में एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत की 'बीबीबी/ए-2' सॉवरेन रेटिंग की पुष्टि की। इससे पहले, 18 वर्षों के अंतराल के बाद 2025 में इसकी दीर्घकालिक रेटिंग को 'बीबीबी' में अपग्रेड किया गया था।

2026-27 की पहली तिमाही (क्यू1) में आर्थिक विकास मजबूत हुआ। यह परिणाम इस तिमाही के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 7.0 प्रतिशत के अनुमान को पार कर गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी या स्थिर कीमतों पर जीडीपी 81.36 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के 6.9 प्रतिशत की तुलना में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

नॉमिनल जीडीपी या वर्तमान कीमतों पर जीडीपी 88.27 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसने विगत वर्ष के 8.1 प्रतिशत की तुलना में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक लेखांकन अवधि में घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। वास्तविक सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) 73.82 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें विगत वर्ष के 7.0 प्रतिशत की तुलना में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

नॉमिनल जीवीए 80.53 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें विगत वर्ष के 8.1 प्रतिशत की तुलना में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) अर्थव्यवस्था में उत्पादकों, उद्योगों या क्षेत्रों के व्यक्तिगत योगदान को मापता है।

संशोधित अनुमान से सुदृढ़ हुई विकास की तस्वीर

विगत तीन वित्त वर्षों के लिए वास्तविक जीडीपी को बढ़ाकर संशोधित किया गया है। संशोधनों से पता चलता है कि पहली तिमाही का प्रदर्शन पूर्ववर्ती अनुमान की तुलना में मजबूत विकास पथ का अनुसरण करता है।

वार्षिक संशोधित अनुमान आधार वर्ष 2022-23 के साथ नए मूल्य और उत्पादन सूचकांकों के उपयोग को दर्शाते हैं। इसमें आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (पीपीआई) और बैंकिंग सर्विसेज प्राइस इंडेक्स

(बीकेएसपीआई) शामिल हैं। इसमें विभिन्न स्रोतों से अद्यतन प्रशासनिक आंकड़े भी शामिल किए गए हैं।

प्रमुख व्यय घटकों में रुझान

पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियों को निवेश में तीव्र वृद्धि, घरेलू खपत में मजबूती और निर्यात में बढ़ोतरी का समर्थन मिला।

व्यय में मजबूती उत्पादन पक्ष पर भी परिलक्षित हुई जिसमें तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हो रहा है।

वास्तविक जीवीए के संदर्भ में तृतीयक क्षेत्र में 2026-27 की पहली तिमाही में 10.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 2025-26 की पहली तिमाही में हुई 8.0 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। इस क्षेत्र में वित्तीय, रियल एस्टेट, आईटी और पेशेवर सेवाओं में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। द्वितीयक क्षेत्र में 2026-27 की पहली तिमाही में 8.6 प्रतिशत का विस्तार हुआ जबकि विगत वर्ष की इसी तिमाही में यह 6.1 प्रतिशत था।

प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत उत्पादन के समर्थन से विनिर्माण में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कई विनिर्माण श्रेणियों ने भी इस तिमाही के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया:

आईआईपी के अंतर्गत 2026-27 की पहली तिमाही में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन भी 15.2 प्रतिशत बढ़ा जबकि एक साल पहले यह 8.8 प्रतिशत था। बुनियादी ढांचे/निर्माण संबंधी सामग्रियों में भी 7.2 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज की गई जो विगत वर्ष के 6.1 प्रतिशत से अधिक है।

मजबूत और स्थिर औद्योगिक गतिविधि

जुलाई 2026 में औद्योगिक उत्पादन में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि विगत वर्ष यह 5.4 प्रतिशत थी। अप्रैल-जुलाई 2026-27 में इसमें विगत वर्ष की समान अवधि के 4.0 प्रतिशत की तुलना में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

जुलाई 2025 की तुलना में जुलाई 2026 में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन 16.1 प्रतिशत बढ़ गया। कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं में 10.0 प्रतिशत और बुनियादी ढांचे और निर्माण सामग्रियों में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

प्रमुख उद्योगों के सूचकांक (आईसीआई) ने जुलाई 2025 की तुलना में जुलाई 2026 में 5.4 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की। अप्रैल-जुलाई 2026-27 के दौरान, आईसीआई में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो विगत वर्ष की इसी अवधि में 1.5 प्रतिशत थी।

निर्यात का मजबूत प्रदर्शन

भारत से वस्तुओं और सेवाओं का कुल मिलाकर किया जानेवाला निर्यात जुलाई 2026 में अनुमानित 80.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया जो जुलाई 2025 की तुलना में 13.31 प्रतिशत अधिक है।

अप्रैल-जुलाई 2026-27 के दौरान संचयी निर्यात का अनुमान 316.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह अप्रैल-जुलाई 2025-26 के दौरान दर्ज 279.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 13.16 प्रतिशत अधिक है। जुलाई 2026 में प्रमुख क्षेत्रों में बैंक ऋण वृद्धि मजबूत हुई।

कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में जुलाई 2025 के 7.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 17.0 प्रतिशत वृद्धि हुई।

उद्योग को ऋण में 20.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो जुलाई 2025 के 6.5 प्रतिशत से अधिक है।

सेवा क्षेत्र को ऋण जुलाई 2025 के 10.2 प्रतिशत की तुलना में 22.9 प्रतिशत बढ़ गया। विनिर्माण, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश तथा कृषि के क्षेत्रों तक 2026 के दौरान शुरू किए गए नीतिगत उपायों ने इन आर्थिक रुझानों को और मजबूत किया है।

मोबाइल फोन निर्माण योजना (जुलाई 2026) का परिव्यय 2030-31 तक 62,500 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य उत्पादन का और विस्तार करना, बेहतर मूल्यवर्धन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है।

जुलाई 2026 में स्वीकृत सेमीकॉन 2.0 का बजट परिव्यय 1,27,500 करोड़ रुपये है। यह चिप डिजाइन और विनिर्माण, उन्नत पैकेजिंग, अनुसंधान, सामग्री, उपकरण और प्रतिभा विकास का समर्थन करता है।

जुलाई 2026 में स्वीकृत, भव्य रसायन योजना का परिव्यय वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3,030 करोड़ रुपये है। यह देश भर में तीन समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना में सहायता करेगा।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 (ईसीएलजीएस 5.0) से पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए 2.55 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण प्रवाह का लक्ष्य रखा गया है। यह लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के लिए 100 प्रतिशत और गैर-एमएसएमई के लिए 90 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करता है।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें...

आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण को 35.07 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति

दुर्ग। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (जी-राम-जी) योजना के तहत जिले के जनपद पंचायत धमधा क्षेत्र में तीन नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन एवं अनुमोदन के बाद जिला पंचायत दुर्ग द्वारा कुल 35.07 लाख के तीन निर्माण कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला पंचायत दुर्ग के सीईओ बजरंग दुबे ने बताया कि स्वीकृति के तहत ग्राम पंचायत पंचदेवरी, सांकरा और मुडपार में एक-एक आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक भवन के लिए 11.69 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

कृष्ण जन्माष्टमी पर बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें

भिलाई। छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेशानुसार इस माह को पड़ने वाले त्यौहार के दौरान निगम क्षेत्र में पशुवध, गृह जीव हत्या एवं समस्त मांस बिक्री केन्द्रो को बंद रखा जायेगा। पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग छ.ग. शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुपालन में नगर पालिक निगम भिलाई के स्वास्थ्य अधिकारी ने आदेश प्रसारित कर इस माह के पड़ने वाले त्यौहार दिनांक 04.09.2026 कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर समस्त पशुवध तथा मांस बिक्री केन्द्रो में प्रतिबंध लगाया गया है।

सेक्टर-9 अस्पताल में सेव अ लाइफ सीपीसीआर कार्यशाला

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग 'सेव अ लाइफ' पहल के अंतर्गत मासिक 'हैंड्स-ओनली सीपीसीआर ' प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस जन-जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय में आपातकालीन हृदयाघात की स्थिति में त्वरित जीवनरक्षक सहायता प्रदान करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा अधिक से अधिक लोगों को सीपीसीआर तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है। यह कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उदय कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संबिता पंडा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

निधन

सैयद अफसरूद्दीन शीराज़

शीराज़ (सैयद अफ़्सरूद्दीन शीराज़) का आज बुधवार संध्या श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में इंतकाल हो गया। वे सईदा परवीन के पति तथा बॉबी एवम सैफ के पिता थे। उन्हें गुरुवार शाम 4 बजे रामनगर कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जनाज़ा उनके निवास डी-1 बंगला, चौहान टाउन, स्मृति नगर से निकलेगा।

गणेश पंडाल संचालकों से जमा कराएंगे स्वच्छता सुरक्षा निधि, सड़क बंद करने पर होगी कार्रवाई

■ दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा आयोजकों एवं आम नागरिकों के लिए आवश्यक गाइडलाइन्स जारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग जिले में आगामी त्यौहारों एवं सार्वजनिक आयोजनों के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों पर पंडालों एवं अस्थाई संरचनाओं के निर्माण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने आयोजकों से क्षेत्रफल एवं संभावित भीड़ के आधार पर स्वच्छता सुरक्षा निधि जमा कराई जाएगी, जिसे आयोजन के बाद स्थल की साफ-सफ्ाई कर वापस सौंपने पर एक सप्ताह के भीतर बिना ब्याज लौटा दिया जाएगा, अन्यथा सफाई न कराने पर राशि राजसात कर सफाई कार्य कराया जाएगा। इसके साथ ही सड़क बंद कर पंड़ाल बनाने वालों पर भी सख्ती की जाएगी।

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि शहर के प्रमुख मागो पर पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की भूमि पर किसी भी आयोजन की अनुमति देने से पूर्व बीएसपी प्रबंधन की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, नगरीय निकायों द्वारा क्षेत्रफ्ल के आधार पर निर्धारित शुल्क लिया जाएगा, जिसकी जानकारी तत्काल कलेक्टर कार्यालय में दी जाएगी और दरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मार्गदर्शिका के तारतम्य में जारी इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल भी सम्मिलित हुए।

अनुमति से पहले पुलिस का अभिमत भी जरूरी

इसी कड़ी में, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए प्रत्येक अनुमति से पूर्व पुलिस विभाग का अभिमत अनिवार्य किया गया है। मार्ग बाधित होने की स्थिति में पुलिस की सहमति से वैकल्पिक मार्ग का निर्धारण कर इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस, तहसीलदार एवं एसडीएम को दी जाएगी और इसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति आदेश में भी रहेगा। वैकल्पिक मार्ग न होने पर आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आयोजकों को अनुमानित संख्या के आधार पर पर्याप्त महिला एवं पुरुष शौचालय बनाने होंगे अथवा नगरीय निकाय पृथक शुल्क लेकर यह व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। सुरक्षा के लिहाज से 5000 वर्ग फीट तक के आयोजन में न्यूनतम 8 तथा उससे अधिक क्षेत्रफ्ल के आयोजनों में उसी अनुपात में अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे (कम से कम 3 दिन के रिकॉर्डिंग बैकअप के साथ) प्रवेश, निकास, पार्किंग, मूर्ति स्थल व मनोरंजन क्षेत्रों को कवर करते हुए लगाने अनिवार्य होंगे।

प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही मिलेगी बिजली की अनुमति

तकनीकी सुरक्षा एवं परिसंपत्ति की सुरक्षा के संबंध में, नगरीय निकाय के अभियंताओं द्वारा संरचनात्मक स्थायित्व एवं विद्युत सुरक्षा का परीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। बिजली कंपनी या बीएसपी विद्युत विभाग से अनापत्ति, अस्थाई कनेक्शन (मीटर सहित) तथा सुरक्षा निधि वापसी से पूर्व नो-ड्यूस प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति या विरूपण से बचाने के लिए 5000 वर्ग फीट तक के आयोजनों हेतु 10,000 रुपये तथा उससे अधिक के लिए 2 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से अग्रिम सुरक्षा निधि जमा ली जाएगी, जिसे आयोजन समाप्ति के 1 सप्ताह बाद स्थल निरीक्षण व पंचनामा उपरांत नुकसान न पाए जाने पर लौटा दिया जाएगा। अग्निशमन उपायों के तहत, पंडालों को स्थिर एवं अग्निरोधी सामग्री से निर्मित करने, बिजली तारों के नीचे निर्माण न करने तथा नगर सेना एवं अग्निशमन सेवाओं से फायर ऑडिट कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

पंडाल स्थल पर एंबुलेंस पहुंचने व्यवस्था बनाने का भी निर्देश

आपातकालीन प्रबंधन एवं पार्किंग व्यवस्था पर जोर देते हुए, पार्किंग, पंडाल, मूर्ति एवं झूला का ले-आउट ऐसा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के लिए निर्बाध पहुंच मार्ग उपलब्ध रहे। पार्किंग की गंभीर समस्या को देखते हुए कुल आवेदित स्थल का न्यूनतम 50 प्रतिशत भाग पार्किंग हेतु आरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है, जो आयोजन स्थल से अधिकतम 50 मीटर की दूरी पर स्थित हो और इसके लिए कोई अवैध पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इसके अलावा, झूलों, मनोरंजन यंत्रों एवं 15 फीट से ऊंची झांकियों/गुफाओं के लिए लोक निर्माण विभाग या संबंधित निकाय के इंजीनियर से तकनीकी सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

निर्धारित मापदंडों के भीतर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था के संदर्भ में, निर्देश दिया गया है कि केवल निर्धारित मापदंडों के भीतर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग होगा तथा अश्लील, आपत्तिजनक या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गानों, भाषणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा; उल्लंघन पर पुलिस द्वारा सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। व्हीकल माउंटेड डी.जे., एम्प्लीफायर तथा बेस का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर/साउंड बॉक्स का उपयोग वर्जित रहेगा, नियम तोड़ने पर उपकरण जब्त कर राजसात किए जाएंगे। साथ ही, आयोजन स्थल एवं विसर्जन यात्रा मार्ग के आसपास पटाखे या आतिशबाजी का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।

मिट्टी से निर्मित प्राकृतिक रंगों वाली मूर्तियों की हो स्थापना

पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से, केवल मिट्टी से निर्मित प्राकृतिक रंगों वाली मूर्तियों की ही स्थापना की जाएगी; पीओपी, प्लास्टिक, थर्माकोल एवं केमिकल डाई का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। आयोजन समितियों की जिम्मेदारी तय करते हुए, पुरुष एवं महिला वालंटियर्स तथा सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती अनिवार्य की गई है, जिनकी सूची परिचय पत्र सहित स्थानीय पुलिस, निकाय व एसडीएम कार्यालय में जमा होगी। रात्रि में भी समिति के कम से कम 2 सदस्य मूर्ति स्थल पर तैनात रहेंगे। पंडालों में मापदंडों के अनुरूप पृथक कतारें होंगी तथा नशे में आने वालों का पूरी तरह से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

विसर्जन व झांकियों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी

विसर्जन स्थलों पर निकाय, बीएसपी एवं नगर सेना द्वारा प्रकाश, क्रेन व गोताखोर बचाव दल की व्यवस्था रहेगी। झांकियों के विसर्जन हेतु पावर हाउस-मुर्गा चौक-सेक्टर 9-तालपुरी चौक-ठगड़ा बांध मार्ग तथा दुर्ग से गंजपारा-मिनीमाता चौक-पुलगांव होते हुए शिवनाथ नदी का मार्ग निर्धारित किया गया है, किसी अन्य मार्ग से प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार, विसर्जन झांकी में केवल 3 वाहन (मूर्ति वाहन, झांकी वाहन, जनरेटर) ही शामिल हो सकेंगे और झांकी की अधिकतम ऊंचाई वाहन सहित 15 फीट निर्धारित की गई है। विसर्जन यात्रा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, भाला, तलवार, डंडा, नकली हथियार या पटाखे रखना व चलाना पूर्णत: वर्जित रहेगा, उल्लंघन पर कार्यवाही होगी।

मजबूत स्थिति में छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम, चारदिवसीय मैच में सधी हुई शुरुआत

रायपुर। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसियेशन द्वारा डॉ. के थिम्मापीयाह मेमोरीयल आमंत्रण किकेट टुर्नामेंट 2026-27 का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें छत्तीसगढ़ की सीनीयर टीम का पहला मैच 1 - 04 सितंबर 2026 को बैगलुरु, कर्नाटक में मध्य प्रदेश के विरुद्ध खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन की समाप्ति तक छत्तीसगढ़ ने अपनी पहली पारी में 74 ओवरों में 4 विकेट खोकर 217 रन बना लिये है। छत्तीसगढ़ ने सधी हुई शुरुआत की तथा पहले विकेट के लिये अनुज तिवारी तथा सानिध्य हुरकत ने 136 रनों की साझेदारी की।

छत्तीसगढ़ की ओर से अनुज तिवारी ने 83 रन तथा सानिध्य हुरकत ने 55 रनों का योगदान दिया। मध्य प्रदेश की ओर से कुमार कार्तिकेय तथा वेंकटेश अययर ने 2-2 विकेट प्राप्त किये। दूसरे दिन की समाप्ति तक छत्तीसगढ़ 73 रनों से पीछे है। इससे पहले मध्य प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया।मध्य प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुये अपनी पहली पारी 93.4 ओवरों में 9 विकेट पर 290 रन बनाकर घोषित कर दी। मध्य प्रदेश की ओर से शुभम शर्मा ने 105 रन तथा यश दुबे ने 69 रनों का योगदान दिया। उनके अतिरिक्त कुमार कार्तिकेय ने 24 रन बनाये। छत्तीसगढ़ की ओर से मयंक यादव तथा संदीप वारीयर ने 3-3 विकेट प्राप्त किये। उनके अतिरिक्त जयंत यादव ने 2 विकेट तथा वासुदेव बरेथ ने 1 विकेट प्राप्त किए।

विद्युत पोल लगने के बाद भी नहीं मिला बिजली कनेक्शन, किसानों ने जनदर्शन में लगाई गुहार

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं

दुर्ग। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अपर कलेक्टर सिल्ली थॉमस भी उपस्थित थीं।

जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 129 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन के दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्राप्त अनेक आवेदनों पर त्वरित संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन कर प्रकरणों की जानकारी ली और तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इसी कड़ी में खुर्सीपार निवासी ने अपने नाम आबंटित पट्टे की भूमि पर हो रहे कथित अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उनकी गैर मौजूदगी में भाई ने उनकी पट्टे की जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी, जिसके बाद संबंधित व्यक्ति द्वारा वहां बने झोपड़े को तोड़कर मकान का निर्माण कराया जा रहा है। विरोध करने पर मारपीट और गाली गलौच करता है। आवेदक ने निर्माण तत्काल रुकवाने और भूमि वापस दिलाने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम भिलाई को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

सेवा सहकारी समिति रसमड़ा ने धान उपार्जन केंद्र के लिए आबंटित भूमि को उपार्जन योग्य बनाने और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।

सेवा सेतु से मात्र 24 घंटे में मिला आय प्रमाण पत्र, आवेदिका ने जताई खुशी

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। डिजिटल तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था से शासकीय सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुँचाने में सेवा सेतु अत्यंत कारगर माध्यम साबित हो रहा हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका अहिवारा की निवासी जागृति साहू को सेवा सेतु के माध्यम से रिकॉर्ड 24 घंटे के भीतर आय प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

हितग्राही जागृति साहू ने बताया कि उन्हें विभिन्न आवश्यक एवं शासकीय कार्यों के लिए आय प्रमाण पत्र की तत्काल आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने विगत 20 अगस्त 2026 को सेवा सेतु केंद्र, नगर पालिका अहिवारा में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन जमा किया था। केंद्र के ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद अगले ही दिन 21 अगस्त 2026 को उनका आय प्रमाण पत्र स्वीकृत होकर जारी कर दिया गया। जागृति साहू ने बेहद कम समय में कार्य पूर्ण होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पहले किसी भी प्रमाण पत्र को बनवाने में काफी समय लगता था और बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब सेवा सेतु के माध्यम से घर के समीप ही सुगम और त्वरित सेवा मिल रही है। 24 घंटे के भीतर डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मिल जाने से उनके समय और श्रम दोनों की बचत हुई है। उन्होंने नागरिकों को एक ही छत के नीचे पारदर्शी और समयबद्ध शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

मानसून एडवेंचर ट्रैकिंग : प्रतिभागियों ने किया दसवीं बारहवीं शताब्दी की ऐतिहासिक पुरातात्त्विक धरोहरों का अवलोकन

■ अंचल केपुरातात्त्विक स्थलों पर केन्द्रित रहा आयोजन

भिलाई। यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया दुर्ग भिलाई इकाई द्वारा पुरातात्त्विक स्थलों पर केन्द्रित एक दिवसीय मानसून एडवेंचर ट्रैकिंग का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों ने दसवीं बारहवीं शताब्दी की ऐतिहासिक पुरातात्त्विक धरोहरों का अवलोकन किया। यूथ हॉस्टल्स के सदस्यों ने जिला मुख्यालय दुर्ग से लगभग 60 - 70 किमी की दूरी पर स्थित पाँच ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण किया।

विस्तृत जानकारी देते हुए संस्था के दुर्ग भिलाई इकाई के प्रेसिडेंट ऋषिकान्त तिवारी ने बताया कि प्रतिभागियों ने इस दरम्यान सीता मन्दिर देवरबीजा, घुघुस राजा मन्दिर देवकर, शिव हनुमान मन्दिर सहसपुर, देऊर मन्दिर गण्डई और घटियारी शिव मन्दिर बिरखा गण्डई का अवलोकन निरीक्षण किया। अंचल में समृद्ध पुरातात्त्विक धरोहरों और उसमें कलात्मक ढंग से उत्कीर्ण जीवन के विविध प्रसंगों को देखकर प्रतिभागी मंत्रमुग्ध हो गये।

संस्था के चेयरमेन के. सुब्रमण्यम और कोषाध्यक्ष हेमलाल देवाँगन ने बताया कि प्रतिभागीगण सीता मन्दिर सरोवर देवरबीजा में प्रवासी पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवास भी देखे। प्रवासी पक्षियों की गतिविधियों को देखकर सभी अत्यन्त रोमांचित हुए। अवलोकन निरीक्षण के क्रम में सदस्यों ने देवकर में प्राचीन राम मन्दिर का भी दर्शनलाभ लिया। राम मन्दिर परिसर में ओम सांई संस्कृत विद्यालय में संस्कृत सप्ताह के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम में भी सभी ने हिस्सा लिया।

इकाई सचिव सुबोध देवाँगन के अनुसार इस ट्रैकिंग में कुल 31 स्त्री पुरुष प्रतिभागियों ने भाग लिया । अधिकतर मन्दिरों में शिवलिंग स्थापित इन पुरातात्त्विक स्थलों की दीवारों पर पत्थरों से सुन्दर नक्काशी की गयी है । युद्ध का वीरतापूर्ण चित्रण , स्त्री पुरुष की सहज कलात्मक अभिव्यक्ति और विभिन्न आसनों में मिथुन मूर्तियों का सूक्ष्म उत्कीर्णन इन मन्दिरों की विशेषताएँ हैं। लगभग सभी स्थल पुरातत्त्व विभाग भारत सरकार अथवा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संरक्षित स्थल घोषित हैं । लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित ये ऐतिहासिक धरोहर अंचल का गौरव हैं। आयोजन को सफल बनाने में अरविन्द ताम्रकार, ओमकुमारी देवाँगन, रूपेश साहू, उषा रानी यादव, प्रसिद्धि यादव, राजेश मराठे, शिल्पा मराठे, कमल साहू, ममता साहू, संजय साहू, सुलेखा साहू, तोरन लाल साहू, तुलसी साहू, लिगेन्द्र वर्मा, अथर्व वर्मा, किशोर छबलानी, राजश्री श्रृंगारपुतले, पल्लवी मेश्राम आदि की भूमिका रही।

माहेश्वरी पटेल को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने दी पीएचडी की उपाधि

भिलाई। माहेश्वरी पटेल को डॉ. विनय कुमार पाठक के समकालीन साहित्य में विविध विमर्श' पर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छत्तीसगढ़) द्वारा हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्रदान कर दी गयी है। यह उपाधि उन्होंने डॉ शंकर मुनीराय प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय राजनांदगाँव (छ.ग.) के निर्देशन में प्राप्त किया। सम्प्रति डॉ माहेश्वरी पटेल अतिथि प्राध्यायक के रूप में कार्यरत हैं। उल्लेखनीय है कि डॉ पाठक ने लगभग सभी विमर्शो पर लेखनी चलाई है। इक्कीसवीं सदी के विकलांग-विमर्श के प्रवर्तक, किन्नर-आलोचना के शिखर तथा कृषक विमर्श के प्रमाणिक प्रथम आलोचक होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। इसके पूर्व डॉ पाठक के योगदान पर एकदर्जन पीएचडी और एक डी-लिट का कार्य भी हो चुका है।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी 376 महिलाओं और 313 पुरुषों को डिग्री मिली

नक्सलवाद के खतरे को मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, दृढ़ सुरक्षा नीति और विकासोन्मुखी शासन के बल पर समाप्त किया गया - उपराष्ट्रपति

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होकर कहा कि यह दीक्षांत समारोह केवल उत्सव का क्षण नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को जो डिग्रियां मिल रही हैं और कल इससे कहीं अधिक मूल्यवान जिम्मेदारी सौंपी जाएगी- भारत की जनता का स्वास्थ्य, विश्वास और जीवन। एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में 376 महिलाओं और 313 पुरुषों को डिग्री प्रदाय की गई। उपराष्ट्रपति ने मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए।

छत्तीसगढ़ समृद्धि, विकास और प्रगति के एक नए युग की ओर अग्रसर

उपराष्ट्रपति ने अपने उदबोधन में आगे कहा कि छत्तीसगढ़ आज अपने अतीत के अंधकार से निकलकर समृद्धि, विकास और प्रगति के एक नए युग की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने इस परिवर्तन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रणनीतिक संकल्प और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रतिबद्ध नेतृत्व को दिया। दशकों से चले आ रहे नक्सली खतरे का अंत हो गया है और जिन क्षेत्रों को कभी हिंसा के लिए जाना जाता था, उन्हें अब सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, रोड़ कनेक्टिविटी, निवेश और अवसरों के लिए जाना जाने लगा है। उन्होंने कहा, यह परिवर्तन इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, दृढ़ सुरक्षा नीति और विकासोन्मुखी शासन में कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता हैं।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी में हुई उल्लेखनीय वृद्धि

विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन को प्राप्त करने के लिए संतुलित विकास के महत्व पर बल देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह दृष्टिकोण तभी साकार हो सकता है, जब प्रत्येक राज्य, जिला और गांव का विकास हो। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा तक पहुंच विकसित भारत की परिकल्पना का मूल आधार है। उन्होंने पिछले बारह वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा के विस्तार पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी में हुई उल्लेखनीय वृद्धि का भी उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2014-15 में महिला नामांकन जहां 1.57 करोड़ था, 2023-24 में यह बढ़कर अब 2.24 करोड़ हो गया, जो 42.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

एम्स रायपुर की बढ़ती प्रतिष्ठा छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय

राज्यपाल ने कहा कि नव-स्नातक चिकित्सकों से स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, नवाचार को प्रोत्साहित करने और चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों, विशिष्ट चिकित्सकीय सेवाओं और अनुसंधान पहलों के माध्यम से संस्थान क्षेत्र के स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एम्स रायपुर की बढ़ती प्रतिष्ठा छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है और यह संस्थान के प्राध्यापकों, चिकित्सा विशेषज्ञों तथा पूरी टीम की उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से चिकित्सा विशेषज्ञता के साथ वैज्ञानिक जिज्ञासा और अनुसंधान आधारित सोच को अपनाने तथा समाज की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन समाधान विकसित करने का आग्रह किया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2012 में स्थापना के बाद से एम्स रायपुर ने मध्य भारत में स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि बेहद कम समय में यह संस्थान छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों के लिए एक प्रमुख तृतीयक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है और ग्रामीण एवं आदिवासी समुदायों तक भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि एम्स रायपुर का विकास छत्तीसगढ़ में हो रहे उल्लेखनीय परिवर्तन को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दशकों से चली आ रही चुनौतियों का जिक्र करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि कठिन भौगोलिक स्थिति, आवागमन की खराब सुविधा और वामपंथी उग्रवाद ने विकास में गंभीर बाधाएं खड़ी की। कई दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में भय और हिंसा ने सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के विकास को बाधित कर दिया, जिससे समुदायों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में दूरी और अभाव का सामना करना पड़ता था। उपराष्ट्रपति ने एम्स रायपुर को नए छत्तीसगढ़ के बेहतरीन प्रतीकों में से एक बताया, जो भय और अभाव के युग से शांति, प्रगति और संभावनाओं के युग की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने उन्नत स्वास्थ्य सेवा और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में संस्थान की उपलब्धियों की भी सराहना की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में किए गए पहले किडनी प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण में 95 प्रतिशत से अधिक सफलता दर, कॉर्नियल प्रत्यारोपण और कान प्रत्यारोपण को महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उल्लेख किया, जो यह दर्शाती हैं कि इस क्षेत्र में उन्नत चिकित्सा कितनी तेजी से सुलभ हो रही है। उन्होंने कहा कि हृदय प्रत्यारोपण कार्यक्रम की मंजूरी एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

स्नातकों को संबोधित करते हुए, उप राष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने युवा स्नातकों से हमेशा दृढ़ता से नशीली दवाओं को न कहने और एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया, जहां प्रौद्योगिकी सभी नागरिकों तक पहुंचे और प्रत्येक युवा भारतीय एक बेहतर भविष्य की आकांक्षा कर सके। उन्होंने कहा आपका ज्ञान स्वास्थ्य प्रदान करे, आपका शोध नवाचार लाए और आपकी सेवा प्रेरणा दे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स रायपुर को नैदानिक उत्कृष्टता, वैज्ञानिक नवाचार, जन स्वास्थ्य और करुणापूर्ण सेवा में निरंतर सफलता की कामना की। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ का रूपांतरण 2047 तक विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनेगा।चिकित्सा का वास्तविक उद्देश्य मानवता की सेवा है और एक चिकित्सक की श्रेष्ठता केवल उसकी पेशेवर दक्षता से नहीं, बल्कि मरीजों के साथ किए जाने वाले व्यवहार, विश्वास और सम्मान से भी निर्धारित होती है।

उन्होंने सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल, सफल एवं संतोषप्रद भविष्य की शुभकामनाएं दीं। दीक्षांत समारोह का प्रमुख आकर्षण विभिन्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थियों को 689 डिग्री प्रमाण-पत्रों का वितरण रहा। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 16 पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

मितानिन बहनें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य तंत्र की मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी: राजेश अग्रवाल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मितानिन बहनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे स्वास्थ्य तंत्र और ग्रामीण समुदाय के बीच मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करते हुए लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

मितानिन बहनें हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य तंत्र की मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। यह बात पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कही।

विधानसभा अंबिकापुर अंतर्गत विकासखंड उदयपुर के रामगढ़ में मंत्री राजेश अग्रवाल ने मितानिन बहनों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने मितानिन बहनों से

आत्मीय चर्चा कर उनके कार्यों, अनुभवों, समस्याओं और आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने में उनके योगदान को सराहा।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में मितानिन बहनें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे गांव-गांव में लोगों के साथ सीधे संपर्क में रहती हैं और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर समुदाय के बीच जागरूकता का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत बनाने में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली मितानिन बहनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी सक्रियता और सेवाभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंच रहा है।

रामगढ़ में आयोजित संवाद के दौरान मंत्री अग्रवाल ने मितानिन बहनों से सीधे बातचीत की और उनके कार्यों से जुड़े अनुभवों को जाना। उन्होंने उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना तथा उनके कार्यों और सेवाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की।

मंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर सेवा देने वाली मितानिन बहनों के अनुभव और सुझाव महत्वपूर्ण हैं। उनके साथ संवाद के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वास्तविक अनुभवों और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलता है। राजेश अग्रवाल ने मितानिन बहनों की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि वे कठिन परिस्थितियों में भी ग्रामीण समुदाय के साथ निरंतर जुड़ी रहती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका सेवा भाव, समर्पण और जमीनी योगदान सराहनीय है।

चेकमेट एट जशपुर अखिल भारतीय ओपन फिडे रेटेड शतरंज प्रतियोगिता का सफल समापन

12 राज्यों के 164 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, विभिन्न श्रेणियों में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

श्रीकंचनपथ समाचार

जशपुर। जशपुर में पहली बार आयोजित 'चेकमेट एट जशपुर दृअखिल भारतीय ओपन फिडे रेटेड शतरंज प्रतियोगिता 2026' का सफलतापूर्वक समापन हुआ। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल के कौस्तुव कुंडू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल विजेता का खिताब अपने नाम किया। छत्तीसगढ़ के यशद बम्बेश्वर ने दूसरा तथा महाराष्ट्र के केदार ओंकार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

पुरानी टोली स्थित कम्युनिटी हॉल में 29 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित इस चार दिवसीय प्रतियोगिता में देश के 12 राज्यों से 164 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने अपनी रणनीतिक क्षमता, एकाग्रता और उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता को रोमांचक बनाया।

समापन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक श्रीमती रायमुनी भगत सहित अन्य अतिथियों ने विभिन्न आयु वर्ग एवं श्रेणियों के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं पुरस्कार राशि के चेक प्रदान कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता का आयोजन जिला प्रशासन, खेल विभाग एवं जशपुर जिला शतरंज संघ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

विधायक रायमुनी भगत ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन, खेल विभाग एवं शतरंज संघ को बधाई दी। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि शतरंज केवल मनोरंजन का खेल नहीं है, बल्कि यह संयम,

एकाग्रता, अनुशासन और बुद्धिकौशल विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना बुद्धिकौशल, अनुशासन और संयम के साथ करते हुए समय की कद्र करने वाला व्यक्ति सफलता की ओर आगे बढ़ता है। शतरंज का खेल भी हमें यही महत्वपूर्ण सीख देता है।

प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सीनियर सिटीजन वर्ग में जवाहरलाल गुप्ता विजेता और सेनगुप्ता दीपांकर उपविजेता रहे।

सरगुजा डिवीजन महिला वर्ग में सिन्हा कशिश ने प्रथम और श्वेता रानी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सरगुजा डिवीजन पुरुष वर्ग में रुद्राक्ष सिंह विजेता और यशवंत सिंह उपविजेता रहे।

जशपुर महिला वर्ग में हेमलता प्रजापति ने प्रथम तथा प्रेमलता साहू ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जशपुर पुरुष वर्ग में एलान लकड़ा प्रथम और श्याम सिंह द्वितीय रहे।

30 वर्ष से अधिक महिला वर्ग में आरती पावले प्रथम तथा लक्ष्मी शुक्ला द्वितीय रहीं। अंडर-15 वर्ग में ईशान सैनी प्रथम और गर्व केरकेट्टा द्वितीय रहे। अंडर-13 वर्ग में शिल्प कुमार घोड़ेश्वर ने प्रथम तथा विराट यादव ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

अंडर-11 वर्ग में वी. विराट अय्यर प्रथम और कुशाग्र दीक्षित द्वितीय रहे। अंडर-09 वर्ग में आद्विक भूषण प्रथम तथा हृदान मावलंकर द्वितीय रहे। महिला खिलाड़ियों की विभिन्न श्रेणियों में एफ-15. वर्ग में प्राची यादव प्रथम और भगत कोमल द्वितीय रहीं। एफ-15 वर्ग में अभिश्री वत्स ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एफ-13 वर्ग में नैना भगत प्रथम रहीं। एफ-11 वर्ग में सावी गौरी प्रथम तथा अनिका रेड्डी गोलुगुरी द्वितीय रहीं। एफ-09 वर्ग में परीक्षिता दुबे प्रथम तथा श्रीनिका रेड्डी गोलुगुरी द्वितीय रहीं।

मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर जशपुर को सड़क विकास की बड़ी सौगात

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल खरकट्टा से कोडेकेला पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 6 करोड़ 30 लाख 81 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वीकृत परियोजना के तहत 6.20 किलोमीटर लंबी सड़क का पुल-पुलिया सहित निर्माण किया जाएगा। इस मार्ग के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य मार्गों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्रवासियों को वर्षभर सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। विशेषकर बरसात के दौरान आवागमन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में पुल-पुलिया सहित सड़क निर्माण महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों तक मजबूत सड़क नेटवर्क पहुंचाने को प्राथमिकता दी जा रही है। बेहतर सड़कें गांवों को केवल मुख्य मार्गों से जोड़ने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और व्यापार जैसी आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच भी आसान होती है। सड़क संपर्क मजबूत होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

अक्टूबर में हर निर्माणाधीन स्थल पर दिखे काम बरसात के बाद युद्धस्तर पर शुरू हो निर्माण

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने बरसात के समाप्त होते ही निर्माणाधीन पुल-पुलियों और राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी निर्माणाधीन कार्यों का एक सप्ताह के भीतर ठेकेदारों के साथ स्थल निरीक्षण कर काम आगे बढ़ाने की अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करते हुए बरसात के तुरंत बाद निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में सभी निर्माण स्थलों पर काम होते हुए दिखना चाहिए।

श्री बंसल ने नवा रायपुर स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय 'निर्माण

भवन' में पुल-पुलियों और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए वर्ष 2025-26 और 2026-27 के प्राथमिकता वाले कार्यों के प्राक्कलन 20 सितम्बर तक जमा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बारिश से क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत के साथ रेलिंग और दीवारों की पेंटिंग का काम 30 नवम्बर तक पूरा करने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में सेतु परिक्षेत्र के सभी संभागों के कार्यपालन अभियंताओं को अपने-अपने संभागों में भ्रमण कर पुल-पुलियों की वास्तविक जरूरत का आकलन कर लोगों की जरूरतों के अनुरूप नए पुल-पुलियों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुराने और क्षतिग्रस्त पुलों की स्थिति पर भी लगातार नजर रखने और जहां आवश्यकता हो, वहां नए पुलों के निर्माण के प्रस्ताव भेजने को कहा।

मरार समाज के उत्थान के लिए समन्वित प्रयास होंगे

कृषि, उद्यानिकी, मंडी, ऊर्जा और जल संसाधन विभाग मिलकर बनाएंगे कार्ययोजना

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता कृषि एवं उद्यानिकी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े गरीब, पिछड़े, लघु और सीमांत किसानों तक पहुंचाना है। इसके लिए कृषि एवं संबद्ध विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए कहा कि यही शाकम्भरी बोर्ड के गठन का मूल उद्देश्य है।

नवा रायपुर स्थित उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालनालय में सोमवार को आयोजित ''छत्तीसगढ़

राज्य शाकम्भरी बोर्ड के संचालक मंडल की पहली बैठक'' को संबोधित करते हुए नायक ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी क्षेत्र में मरार समाज का योगदान ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री नायक ने कहा कि भले ही शाकम्भरी बोर्ड का गठन मरार-पटेल समाज के उत्थान के उद्देश्य से किया गया है, लेकिन बोर्ड की सोच सभी किसानों के हित और समृद्धि से जुड़ी है।

कृषि, उद्यानिकी, जल संसाधन, ऊर्जा, वाणिज्य एवं उद्योग तथा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के समन्वित प्रयासों से किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। बैठक में लघु एवं सीमांत किसानों को उद्यानिकी फसलों तथा विशेष रूप से पुष्प उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने, योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने तथा जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के माध्यम से पात्र किसानों को अधिकाधिक लाभान्वित करने पर भी सहमति बनी।

बैठक में बोर्ड के सदस्य बसंत पटेल, प्रेमलाल पटेल,संतोष पटेल और प्रेम पटेल सहित उद्यानिकी विभाग के संचालक लोकेश कुमार तथा शाकम्भरी बोर्ड के सचिव सुरेश ठाकुर, संयुक्त सचिव राजीव अहारे, सहायक अभियंता सिद्धार्थ पाण्डेय, कृषि जितेन्द्र ठाकुर तथा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता सी.एल. देवांगन एवं सी.बी. ध्रुव सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

करेले की खेती से नारायण प्रसाद की आय में आई हरियाली

श्रीकंचनपथ समाचार

महासमुंद। महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड के ग्राम टेंगराही के कृषक नारायण प्रसाद वर्मा ने पारंपरिक धान की खेती के साथ उद्यानिकी फसलों को अपनाकर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के सहयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग से उनकी खेती अब अधिक लाभकारी हो गई है। वर्मा क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं।

नारायण प्रसाद वर्मा के पास कुल 1.06 हेक्टेयर कृषि भूमि है। पहले वे मुख्य रूप से धान की खेती करते थे, जिससे उन्हें अपेक्षाकृत सीमित आय प्राप्त होती थी। खेती को अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से उन्होंने उद्यानिकी फसलों की ओर कदम बढ़ाया और करेला सहित अन्य सब्जियों की खेती शुरू की।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना में श्री वर्मा को एक हेक्टेयर क्षेत्र में करेला की खेती के लिए 24 हजार रुपये का अनुदान प्रदान किया गया। इसके साथ ही सब्जी फसलों के लिए 0.50 हेक्टेयर क्षेत्र में सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने हेतु 5 हजार रुपये का अनुदान भी डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में मिला।

सरकारी सहयोग के साथ उन्होंने खेती में ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और आधुनिक कृषि यंत्रों जैसी तकनीकों को अपनाया। इन तकनीकों से पानी की बचत हुई और फसल की गुणवत्ता एवं उत्पादन में भी सुधार आया।

गंजेपन से मुक्ति
मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी
पहले बाद में
JITU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बेंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0788-4060131
अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

कॉमेडी में फिर वापसी कर रहीं ईशा

इस फिल्म में आएंगी नजर, बोलीं- 'मुझे इस समय बिल्कुल यही चाहिए था'

ईशा देओल एक बार फिर कॉमेडी जॉनर में वापसी कर रही हैं। एक्ट्रेस का कहना है कि वह काफी समय से एक हल्की-फुल्की और मजेदार फिल्म करना चाहती थीं। जानिए किस फिल्म में नजर आएंगी ईशा।

ईशा देओल एक बार फिर उस जॉनर में वापसी कर रही हैं, जिसे वह हमेशा से पसंद करती रही हैं। एक्ट्रेस ने फिल्म पर बात करते हुए एक्साइटमेंट जाहिर की है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।

इस फिल्म में नजर आएंगी ईशा

ईशा देओल अब 'मालामाल वीकली 2' में नजर आएंगी। यह एक कॉमिक कैपर यानी मजेदार और मनोरंजन से भरपूर फिल्म है। ईशा के लिए यह फिल्म बिल्कुल सही समय पर आई है। इससे पहले वह दो बिल्कुल अलग तरह की फिल्मों पर काम कर चुकी हैं- हॉरर-कॉमेडी 'घूंघट' और तेलुगु फिल्म 'SYG'।

ईशा ने कहा, 'मुझे इस समय बिल्कुल यही चाहिए था- कुछ मजेदार, हल्का-फुल्का और हंसी से भरपूर। अभी मैंने दो बिल्कुल अलग तरह की फिल्में पूरी की हैं- हॉरर-कॉमेडी 'घूंघट' और तेलुगु फिल्म 'SYG'। इसके बाद मैं एक पूरी तरह की कॉमिक कैपर फिल्म करना चाहती थी और 'मालामाल वीकली 2' बिल्कुल सही समय पर मेरे पास आई।'

इन फिल्मों में भी कर चुकी हैं कॉमेडी

ईशा देओल इससे पहले 'नो एंट्री', 'शादी नं. 1' और 'वन टू थ्री' जैसी कॉमेडी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। एक्ट्रेस का कहना है कि कॉमेडी हमेशा से उनके दिल के करीब रही है। ईशा ने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट ने उन्हें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए सबसे ज्यादा आकर्षित किया।

उन्होंने कहा, ''नो एंट्री', 'शादी नं. 1' और 'वन टू थ्री' जैसी फिल्में करने के बाद कॉमेडी एक ऐसा स्पेस है, जिसे मैंने हमेशा पसंद किया है और जिसमें मैं वापस आना चाहती थी। इसकी स्क्रिप्ट बहुत मजेदार है और मुझे सच में लगता है कि हर कोई इसे पसंद करेगा। मैं बहुत खुश हूं कि मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा हूं, जो पूरी तरह मस्ती, हंसी और मनोरंजन से भरपूर है।'

रितेश से एल्विश तक, ये सितारे आएंगे नजर

बता दें कि 'मालामाल वीकली 2' की कास्ट को लेकर अब तक सामने आई रिपोर्ट्स में रितेश देशमुख, परेश रावल, राजपाल यादव, एल्विश यादव, रवीना टंडन, परिणीति चोपड़ा, शिल्पा शिरोडकर, फरदीन खान के नाम शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' फेम अमित जोशी करेंगे और इसकी शूटिंग नवंबर से शुरू हो सकती है।

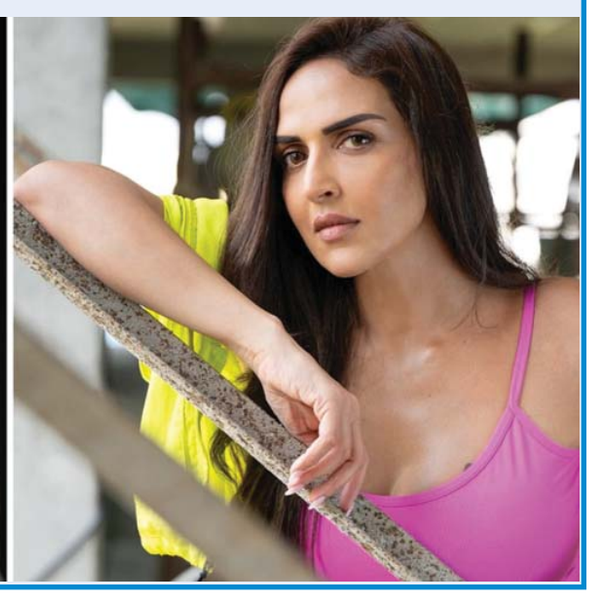

बैंगनी और सफेद साड़ी में मोनालिसा ने फैंस को चौंकाया

मोनालिसा ने एक बार फिर अपने फैंस को अपनी तस्वीरों से चौंका दिया है। अभिनेत्री ने साड़ी में कई बेहतरीन पोज दिए हैं। उनके फैंस तस्वीरों की सराहना कर रहे हैं। भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने सफेद और बैंगनी रंग की साड़ी में कई शानदार पोज दिए हैं। उनकी तस्वीरों पर उनके फैंस अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

मोनालिसा की पोस्ट में क्या है?

अभिनेत्री मोनालिसा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें देखा जा सकता है कि उन्होंने सफेद और बैंगनी रंग की साड़ी में कई तस्वीरें शेयर की हैं। साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग ज्वेलरी पहनी है। उन्होंने खुले बालों से अपने लुक को पूरा किया है।

इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनको देखने से लगता है कि अभिनेत्री ने किसी पार्क में पोज दिए हैं। एक तस्वीर में वह पार्क में लगे झूले को पकड़ कर पोज दे रही हैं। इसमें वह अपना बैक साइड फ्लॉन्ट कर रही हैं। वहीं एक और तस्वीर में वह सामने से अपना स्टाइल दिखा रही हैं।

तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा 'जब आपका दिल खुश हो और आपका दिमाग फ्री हो।' अभिनेत्री की तस्वीरों पर कई फैंस ने कमेंट किए हैं। एक यूजर ने उन्हें खूबसूरती की रानी कहा है। एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'मैम आप बहुत मसूम और खूबसूरत दिखती हो।'

आपको बता दें कि मोनालिसा भोजपुरी स्टार हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वह यहां अक्सर अपनी शानदार तस्वीरें शेयर करती रही हैं। 43 साल की उम्र में वह काफी फिट हैं। हाल ही में वह शो 'द 50' में नजर आ चुकी हैं।

तापसी को गंभीर रोल में देखकर क्यों चौंक जाते हैं स्कूल-कॉलेज के दोस्त? एक्ट्रेस ने खुद बताई वजह

तापसी पन्नू इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'गांधारी' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बीच अभिनेत्री ने से खास बातचीत में कॉमेडी जॉनर को लेकर बात की। तापसी पन्नू ने अब तक कई गंभीर किरदार निभाए हैं, लेकिन उनके स्कूल-कॉलेज के दोस्तों को आज भी उन्हें ऐसे रोल में देखना थोड़ा अजीब लगता है। तापसी बताती हैं कि वे लोग उन्हें हमेशा से अलग अंदाज में जानते हैं और चाहते हैं कि वह कॉमेडी भी करें।

'लोगों को यकीन करना मुश्किल होता है कि मैं इतने सीरियस रोल करती हूं'

तापसी कहती हैं, 'मुझे लगता है कि कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है, जिसे मैंने अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, खासकर स्कूल और कॉलेज के समय से, उन्हें यह विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है कि मैं इतने सीरियस रोल करती हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी सीरियस देखा ही नहीं है।'

वह आगे कहती हैं, 'उनके लिए यह देखना बहुत मुश्किल है कि मैं इतना हैवी लिफ्टिंग और इतना इंटेंस इमोशन करती हूं। उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में ऐसा कभी करते नहीं देखा। तो उनके लिए यह बहुत बड़ा शॉक है। जो लोग मुझे पर्सनल लेवल पर जानते हैं, वे चाहते हैं कि मैं कॉमेडी करूं।'

'कॉमेडी का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहती'

तापसी का मानना है कि महिला के नजरिए से कॉमेडी को अभी उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है। वह कहती हैं, 'मुझे लगता है कि हमने अभी तक एक महिला के नजरिए से कॉमेडी को उतना एक्सप्लोर नहीं किया है। मुझे नहीं पता क्यों... हालांकि, मैं कॉमेडी का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहती, मैं कॉमेडी करना चाहती हूं।'

'कॉमेडी करने के लिए 'खेल खेल में' चुनी'

इसी वजह से उन्होंने मल्टीस्टारर फिल्म 'खेल खेल में' भी की। तापसी कहती हैं, 'मैंने उसमें थोड़ा अलग तरह का मजाकिया किरदार करने की कोशिश की थी। उस फिल्म को करने की एक बड़ी वजह यही थी कि मैं इस जॉनर को आजमाना चाहती थी। वो वाकई एक अलग तरह की फिल्म थी।

एंटीक ज्वैलरी देगी हरेक ड्रेस को रॉयल लुक

एंटीक ज्वैलरी का फैशन सदाबहार है। इसकी खूबसूरती और रॉयल अंदाज हर आउटफिट को खास बना देता है। विंटेज डिजाइन, गोल्डन फिनिश, कुंदन, मोती और ट्रेडिशनल मोटिफ्स इसे बाकी एक्सेसरीज से अलग बनाते हैं। महिलाएं इसे साड़ी-लहंगे के साथ ही नहीं, कुर्ती, सूट और वेस्टर्न ड्रेस संग भी स्टाइल कर रही हैं। जब आप कोई ड्रेस पहनती हैं तो आपको उसके अनुसार ज्वैलरी को भी कैरी करना होता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपका लुक प्रॉपर नजर नहीं आएगा। जानिये एंटीक ज्वैलरी के बारे में कि किस तरह से आप इस ज्वैलरी को कैरी करके अपने आउटफिट को शानदार लुक दे सकती हैं।

एंटीक नेकलेस साड़ी को बनाएगा खास

यदि आपको अपनी साड़ी को एक खास लुक देना है तो एंटीक नेकलेस कैरी करें। इसका लुक आपको एलिगेंट अंदाज देगा। सिल्क, बनारसी, कॉटन या ऑर्गेंजा साड़ी के साथ एंटीक गोल्ड नेकलेस आपके पूरे लुक को रॉयल टच दे सकता है। अगर साड़ी हैवी है तो मीडियम साइज का नेकलेस चुनें और अगर साड़ी सिंपल है तो थोड़ा हैवी नेकपीस ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ छोटे झुमके या स्टड ईयररिंग्स पहनें, ताकि लुक जरूरत से ज्यादा भारी न लगे।

ऑक्सीडाइज्ड ज्वैलरी व कुर्ती

यदि आप सिंपल कुर्ती पहनकर जा रही हैं और आपको लगता है कि कुछ ऐसी ज्वैलरी कैरी की जाए जिससे वह डिफरेंट बन जाए तो इसके लिए एंटीक चोकर या ऑक्सीडाइज्ड नेकलेस ट्राई करें। प्लेन व्हाइट, ब्लैक, बेज, ग्रीन या मरून कुर्ती के साथ कॉन्ट्रास्टिंग एंटीक ज्वैलरी काफी खूबसूरत लगेगी। इसके साथ जूतियां और छोटा हैंडबैग कैरी करके आप ऑफिस से लेकर कैजुअल आउटिंग तक के लिए स्टाइलिश लुक पा सकती हैं।

एंटीक ज्वैलरी वेस्टर्न ड्रेस पर भी जंचेगी

एंटीक ज्वैलरी की खासियत है कि वह सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेस को ही खास लुक नहीं देती, बल्कि वेस्टर्न ड्रेस पर भी खूब जंचती है। ब्लैक, व्हाइट या सॉलिड कलर की वेस्टर्न ड्रेस के साथ एंटीक स्टेटमेंट नेकलेस पहनकर आप एक खूबसूरत इंडो-वेस्टर्न लुक क्रिएट कर सकती हैं।

अगर ड्रेस की नेकलाइन सिंपल है, तो हैवी नेकपीस अच्छा लगेगा। वहीं हाई नेक या ज्यादा डिजाइन वाली ड्रेस के साथ स्टेटमेंट ईयररिंग्स बेहतर विकल्प हैं।

झुमके देंगे कानों को खूबसूरती

कई बार ऐसा होता है कि गले में ज्वैलरी पहनने का मन नहीं होता है, तो ऐसे में आप सिर्फ कानों में भी ज्वैलरी को कैरी कर सकती हैं। बड़े झुमके खासतौर पर साड़ी, अनारकली और एथनिक ड्रेस के साथ अच्छे लगते हैं।

सिंपल ड्रेस के साथ बड़े झुमके पहनने पर चेहरे पर भी ध्यान जाता है और लुक ज्यादा ग्लैमरस दिखाई देता है। तो एंटीक झुमकों को अपनी ज्वैलरी में जरूर शामिल करें।

एंटीक ब्रेसलेट और कड़े

जब आप कानों में या फिर गले में एंटीक ज्वैलरी कैरी करती हैं तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हाथों में भी कुछ एंटीक कैरी किया जाए। तो ऐसे में आप एंटीक ब्रेसलेट या फिर कड़े पहन सकती हैं। स्लीवलेस ड्रेस या शॉर्ट-स्लीव आउटफिट के साथ स्टेटमेंट ब्रेसलेट अच्छा लगेगा, जबकि एथनिक ड्रेस के साथ एंटीक कड़ों की लेयरिंग की जा सकती है।

आउटफिट हैवी और मिनिमल ज्वैलरी

जरूरी है कि सिंपल ड्रेस के साथ हैवी एंटीक ज्वैलरी ट्राई करें। यदि आपका आउटफिट हैवी है तो उसके साथ मिनिमल ज्वैलरी चुनें। ड्रेस और ज्वैलरी के रंगों में अच्छा कॉन्ट्रास्ट रखें। एक साथ बहुत सारे स्टेटमेंट पीसेज पहनने से बचें। फंक्शन के लिए चोकर, झुमके और मांग टीका का कॉम्बिनेशन चुन सकती हैं। कैजुअल लुक के लिए सिर्फ एंटीक ईयररिंग्स या पेंडेंट काफी हैं। वेस्टर्न ड्रेस के साथ एंटीक ज्वैलरी पहनकर इंडो-वेस्टर्न लुक क्रिएट करें।

जब छह महीने खाली बैठे रहे सलमान तब पिता ने की थी मदद

बोले- 'सारा क्रेडिट भाग्यश्री ले गईं'

सलमान खान का करियर फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा चमकता रहा है। मगर बहुत कम लोग यह जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद भी उनके पास काम नहीं था। सलमान खान बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। एक्टर का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर अक्सर सेलेब्स के इंटरव्यू वायरल होते रहते हैं। मगर सलमान खान की 'आप की अदालत' में हुई एक पुरानी बातचीत की क्लिप फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। मैंने प्यार किया' एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी।

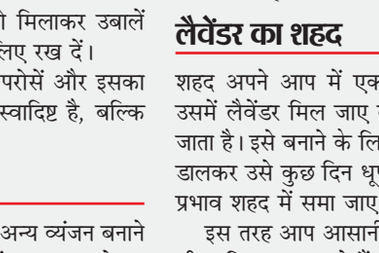

इस फिल्म के बाद मुझे 6 महीनों तक कोई काम नहीं मिला। उसी समय भग्यश्री ने फिल्मी दुनिया छोड़ने का निर्णय ले लिया। वह एक्टिंग को छोड़ अपना घर बसाना चाहती थीं। उनके इस फैसले से मुझे लगा कि अब मुझे काम मिलेगा भी नहीं। उन्होंने शादी कर ली और फिल्म का सारा क्रेडिट ले गईं। सबको लगा कि वह मुख्य किरदार थीं।

पति सलीम खान ने किया सपोर्ट

अपनी बातचीत में सलमान ने आगे बताया कि उनके पिता सलीम खान ने उस मुश्किल दौर में उनकी मदद की। उनके पिता ने फिल्ममेकर जीपी सिप्पी को फोन किया। इसके साथ ही उनसे रहा कि वह यह घोषणा करें कि वह जल्द सलमान को अपनी फिल्म के लिए साइन करेंगे। सिप्पी ने ऐसा ही किया इसके बाद एक्टर के लिए चीजें कुछ आसान हो गईं।

सलमान खान वर्कफ्रंट

अभिनेता सलमान खान एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उनकी अगली फिल्म नयनतारा के साथ एक पैन-इंडिया एक्शन फिल्म है। निर्देशन वामशी पैदिपल्ली ने किया है। फिल्म सलमान और नयनतारा की इस फिल्ममेकर के साथ पहली बार काम करने वाली फिल्म है। इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट के लिए ईद 2027 में थिएटर रिलीज की तारीख तय कर ली है।

खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है लैवेंडर, इससे बनाएं ये 5 व्यंजन

लैवेंडर एक सुगंधित और औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल अरोमाथेरेपी और त्वचा की देखभाल के उत्पादों में किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि लैवेंडर को खाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हां, लैवेंडर खाने में भी काफी उपयोग होने लगा है। इस लेख में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप लैवेंडर को अपनी रसोई में शामिल कर सकते हैं और इससे क्या-क्या व्यंजन बना सकते हैं।

लैवेंडर की चाय

लैवेंडर की चाय एक बेहतरीन पेय है, जो आपको आराम और शांति प्रदान करता है। इसे बनाने के लिए एक कप पानी में कुछ लैवेंडर के फूल डालें और उसे उबालें। जब पानी हल्का नीला हो जाए तो इसे छानकर कप में डालें और इसमें शहद मिलाकर पिएं। यह चाय तनाव कम करने में मदद करती है और नींद लाने में भी सहायक है।

इसके नियमित सेवन से आपका मन शांत रहता है और आप ताजगी महसूस करते हैं।

लैवेंडर की आइसक्रीम

गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम कौन नहीं पसंद करता? अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो घर पर ही लैवेंडर की आइसक्रीम बना सकते हैं।

इसके लिए दूध, मलाई, चीनी और लैवेंडर का इस्तेमाल करें। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर उबालें और ठंडा होने दें, फिर इसे जमने के लिए रख दें।

जब आइसक्रीम जम जाए तो इसे परोसें और इसका आनंद लें। यह आइसक्रीम न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

लैवेंडर का सिरका

सिरके का इस्तेमाल सलाद ड्रेसिंग और अन्य व्यंजन बनाने में किया जाता है। अगर आप सिरके में कुछ नया जोड़ना चाहते हैं तो लैवेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके लिए सफेद सिरके में सूखे लैवेंडर के फूल डालकर उसे धूप में रखें, ताकि उसका स्वाद अच्छे से निकल आए। यह सिरका आपके व्यंजनों को एक अनोखा स्वाद देगा।

आप इस सिरके को सलाद ड्रेसिंग में, सॉस में या फिर किसी भी तरह की ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं।

लैवेंडर का बिस्किट

बिस्किट बनाने के लिए मैदा, मक्खन, चीनी और सूखे लैवेंडर के फूलों का इस्तेमाल करें। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर आटा गूंथ लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर ओवन में सेंक लें।

ये बिस्किट चाय या कॉफी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आते हैं। इन बिस्किट को आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं या फिर किसी भी समय खा सकते हैं।

लैवेंडर का शहद

शहद अपने आप में एक सेहतमंद चीज है और अगर उसमें लैवेंडर मिल जाए तो उसका फायदा कई गुना बढ़ जाता है। इसे बनाने के लिए शहद में सूखे लैवेंडर के फूल डालकर उसे कुछ दिन धूप में रखें, ताकि उसका सुगंधित प्रभाव शहद में समा जाए।

इस तरह आप आसानी से अपनी रसोई में लैवेंडर को भी शामिल कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ भी उठा सकते हैं।

खास-खबर

बस्तर के युवाओं को मिलेगा बड़ा मंच

जगदलपुर। बस्तर संभाग की खेल प्रतिभाओं को निखारने और युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा बस्तर ओलंपिक 2026-27 के भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई है। इस महत्वाकांक्षी खेल महाकुंभ को लेकर कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह ने संभाग के सभी जिला कलेक्टरों और खेल अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तर अंचल के युवाओं में खेलों के प्रति अपार नैसर्गिक क्षमता मौजूद है, जिसे सही दिशा और अवसर देकर उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में तैयार करना तथा शासन व जनता के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना इस आयोजन का मुख्य ध्येय है। कमिश्नर बस्तर के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संभाग के सातों जिलों बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में कुल 11 खेल विधाओं में यह प्रतियोगिता तीन स्तरों पर आयोजित की जाएगी।

अग्निवीर भर्ती रैली के लिए एडमिट कार्ड जारी

कवर्धा । सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 12 जनवरी से 18 जनवरी 2027 तक बहतराई स्टेडियम, बिलासपुर में किया जाएगा। इस भर्ती रैली में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी एवं अग्निवीर ट्रेड्समैन पदों के लिए अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसी प्रकार अग्निवीर क्लर्क पदों के लिए भर्ती का आयोजन 11 अक्टूबर 2026 को इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, सागर (मध्यप्रदेश) में किया जाएगा। इसमें सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के वे अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे, जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सफ्लतापूर्वक उत्तीर्ण किया है।

सेवा सेतु बन रहा ग्रामीणों के लिए सुविधा का माध्यम

कोण्डागांव। जिले में नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ आसानी और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित सेवा सेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए उपयोगी माध्यम साबित हो रहा है। अब विभिन्न आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज बनवाने के लिए ग्रामीणों को बार-बार जिला मुख्यालय अथवा शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। गांव में स्थापित अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिक अपने आवश्यक दस्तावेज जमा कर घर के नजदीक ही विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आवश्यक दस्तावेज अटल डिजिटल सेवा केंद्र में जमा करने के बाद उन्हें लगभग एक सप्ताह के भीतर विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। कश्यप दिव्यांग हैं।

पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्यप्रणाली पर जोर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सत्यनिष्ठा से समृद्धि थीम पर आयोजित कार्यशाला में आचरण नियमों, सतर्कता संबंधी प्रक्रियाओं तथा सीटीई निरीक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए एनएचएआई के मुख्य सतर्कता अधिकारी आशीष नाथ ने कहा कि सतर्कता केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कार्यप्रणाली में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसियों से अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ करने पर जोर दिया।

मेट्स यूनिवर्सिटी, रायपुर के कुलपति प्रो. डॉ. के.पी. यादव ने अपने व्याख्यान में कार्यस्थल पर नैतिकता, ईमानदारी और जिम्मेदार आचरण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान की दीर्घकालिक सफ्लता के लिए व्यावसायिक दक्षता के साथ नैतिक मूल्यों का पालन भी आवश्यक है।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के सेवानिवृत्त अतिरिक्त महानिदेशक श्याम सुंदर पोरवाल ने अपने संबोधन में अनुशासन, ईमानदारी और जवाबदेही को प्रभावी कार्यप्रणाली का आधार बताया। उन्होंने कहा कि निर्माण एवं अधोसंरचना से जुड़े कार्यों में पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया और निर्धारित मानकों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर, एनएचएआई आलोक कुमार ने कहा कि सड़क एवं राजमार्ग निर्माण जैसे बड़े सार्वजनिक कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को बेहतर ढंग से संपादित करने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कन्सेशनायर, अथॉरिटी इंजीनियर्स एवं कांट्रेक्टर सहित सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय और स्पष्ट जवाबदेही आवश्यक है। प्रत्येक स्तर पर निर्धारित प्रक्रियाओं, तकनीकी मानकों एवं नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सतर्कता संबंधी जागरूकता से सभी संबंधित पक्षों में अपने दायित्वों के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना मजबूत होती है तथा पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिलता है। सतर्कता केवल अनियमितताओं की रोकथाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का माध्यम है, जिसमें ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।

कार्यशाला में एनएचएआई मुख्यालय के सतर्कता विभाग ने सतर्कता मामलों से संबंधित प्रक्रियाओं, शिकायतों के प्रभावी निपटारे तथा मुख्य तकनीकी परीक्षक के निरीक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों एवं इंजीनियरों को सतर्कता संबंधी दिशा-निर्देशों के व्यवहारिक अनुपालन और आवश्यक सावधानियों से अवगत कराया।

माइनिंग से हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग तक, छत्तीसगढ़ लगा रहा दांव

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान लंबे समय से खनिज और प्राथमिक प्रसंस्करण पर आधारित रही है। अब राज्य इस पहचान को बदलते हुए कच्चे संसाधनों की बजाय वैल्यू एडेड और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंगका केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार की औद्योगिक रणनीति में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, रक्षा उपकरण, एआई और ग्रीन स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रमुखता दी जा रही है।

राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में इस बदलाव का आधार तैयार किया गया है। इस नीति में स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और उनके मूल्य संवर्धन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा, रक्षा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को केवल खनिजों का आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि तैयार उत्पादों और उन्नत तकनीक आधारित उद्योगों का केंद्र बनाना है।

औद्योगिक नीति लागू होने के बाद से राज्य में निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ी है। राज्य के निवेश प्रोत्साहन पोर्टल के अनुसार पिछले करीब 18 महीनों में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावप्राप्त हुए हैं। इनसे 1.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। खास बात यह है कि इन प्रस्तावों का बड़ा हिस्सा पारंपरिक खनिज आधारित उद्योगों से आगे बढ़कर एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मा, टेक्सटाइल और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे विशेष क्षेत्रों से जुड़ा है। नवा रायपुर में एआई और डेटा सेंटर से जुड़े निवेश तथा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव राज्य की बदलती औद्योगिक दिशा को दर्शाते हैं। इसी क्रम में राजनांदगांव मेंइलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी मिली है। इससे 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और करीब 9,000 प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार आने की उम्मीद है।

फार्मास्यूटिकल्स भी राज्य की नई औद्योगिक तस्वीर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। पिछले 18 महीनों में फार्मा क्षेत्र में करीब 992.53 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावआए हैं, जबकि 216 करोड़ रुपये के चार प्रोजेक्ट कार्यान्वयन के चरण में हैं।इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से विस्तार हो रहा है। केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत देशभर में 69 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है।

छत्तीसगढ़ में श्वस्ट्र 2.0 जैसी पहल इस राष्ट्रीय सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का अवसर देती है। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास की रणनीति केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं है।

स्टील से आगे ग्रीन स्टील की ओर

स्टील उत्पादन में मजबूत आधार रखने वाला छत्तीसगढ़ अब इस क्षेत्र में भी अगली पीढ़ी के उत्पादन पर जोर दे रहा है। देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने और हरित विनिर्माण को बढ़ावा देने के बीचग्रीन स्टीलराज्य के लिए बड़ा अवसर बनकर उभरा है। पिछले महीने आयोजित छत्तीसगढ़ ग्रीन स्टील डायलॉग के दौरान करीब 13,840 करोड़ रुपये के निवेश प्रतिबद्धताओंने इस क्षेत्र की संभावनाओं को मजबूत किया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई जैसी योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ अपने खनिज संसाधन, मौजूदा स्टील उद्योग और ऊर्जा आधार का इस्तेमाल उच्च मूल्य वाले स्टील उत्पादों के निर्माण में कर सकता है।

अबुझमाड़ की नई सुबहः जब जंगलों की छांव से निकलकर स्वावलंबन की मिसाल बनीं नारायणपुर की महिलाएं

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बस्तर के सुदूर और दुर्गम अबुझमाड़ के जंगलों से अब बदलाव की एक नई बयार बह रही है। कभी नक्सल के साए और सिर्फ घरेलू चौखट तक सीमित रहने वाली नारायणपुर तथा ओरछा विकासखण्ड की ग्रामीण महिलाएं अब अपने हौसले और कड़ी मेहनत से आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। वन विभाग की एक दूरदर्शी पहल ने इन महिलाओं के सपनों को न सिर्फ पंख दिए हैं, बल्कि चक्रिय निधि के माध्यम से उन्हें वित्तीय संबल देकर सफ्ल उद्यमी के रूप में उभारने का काम किया है।

वर्ष 2026-27 में शासन की मंशानुरूप क्षेत्र के 10 महिला स्व-सहायता समूहों को 37 लाख रुपये की चक्रिय निधि से ऋण उपलब्ध कराया गया। इस आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंक दी। जय बिहान, जगदम्बा, मां लक्ष्मी, मां शीतला, मां दंतेश्वरी, मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां अम्बे और जय वाला कारयो जैसे समूहों से जुड़ी दीदियां आज विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जुड़कर अपने पैरों पर खड़ी हैं। कोई जंगलों से इमली और माहुल पत्ता चुनकर दोना-पत्तल बना रही है, तो कोई कच्चे फूलझाड़ू का प्रसंस्करण कर बाजार तक पहुंचा रही है। गृह उद्योग के तहत मसाला निर्माण, बेकरी, कैंटीन और किराना स्टोर के सफ्ल संचालन से इन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि अवसर मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में कमाल कर सकती हैं।

इस बदलाव का सबसे खूबसूरत पहलू इन परिवारों के जीवन में आई खुशहाली है। स्वरोजगार से मिल रही नियमित आय ने महिलाओं के भीतर न केवल आत्मविश्वास जगाया है, बल्कि अब वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने में सक्षम हो पाई हैं।

बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान विद्यार्थियों ने लिया बाल विवाह के खिलाफ संकल्प

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के उन्मूलन और बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी एवं हाई स्कूल कुलीपोटा में बाल विवाह रोकथाम एवं बाल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों तथा इसके सामाजिक प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र जायसवाल ने बताया कि बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बालिका की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष तथा बालक की न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित आयु से पहले विवाह कराना अथवा उसमें सहयोग करना कानूनन दंडनीय अपराध है।

चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने विद्यार्थियों को बताया कि यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिले अथवा किसी नाबालिग बच्चे या बच्ची का विवाह कराया जा रहा हो, तो इसकी सूचना तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग को दी जानी चाहिए।

गुदुम बाजा और मोहरी की पारंपरिक धुनों से सजा 'रंग-तरंग'

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक लोकवाद्यों और लोक कलाओं की मनमोहक प्रस्तुतियों से तीन दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन 'रंग-तरंग' का दूसरा दिन जीवंत हो उठा। लोकवाद्य गुदुम बाजा और मोहरी की पारंपरिक धुनों ने आयोजन स्थल पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति की विशिष्ट छटा बिखेरी और उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कार्यक्रम में पूर्व संस्कृति आयुक्त अनिल कुमार साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों और बच्चों से आत्मीय मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने लोक कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने तथा नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कलाकारों और आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी साहित्य से जुड़े विजय मिश्रा, समाजसेवी उदयभान, वरिष्ठ पत्रकार एवं छायाकार दीपेंद्र दीवान सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

'रंग-तरंग' के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं, साहित्य, संगीत और कला को एक साझा मंच प्रदान किया जा रहा है। आयोजन में पारंपरिक लोकवाद्यों की मधुर धुनों और कलाकारों की प्रस्तुतियों ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। लोक संस्कृति से जुड़े इस आयोजन को संस्कृति प्रेमियों और दर्शकों की सराहना मिल रही है।

दक्षिण भारत के पर्यटन बाजार में छत्तीसगढ़ ने बढ़ाया कदम

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के चेन्नई रोड शो में टूर ऑपरेटर्स से सीधा संवाद, छत्तीसगढ़ भ्रमण के लिए पर्यटकों को जोड़ने पर जोर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन को दक्षिण भारत के प्रमुख पर्यटन बाजार से जोड़ने और राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की दिशा में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने चेन्नई में छत्तीसगढ़ टूरिज्म रोड शो का भव्य आयोजन किया। फिक्की के सहयोग से आयोजित इस रोड शो में चेन्नई के 130 से अधिक ट्रैवल एजेंट एवं टूर ऑपरेटरों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित बिजनेस-टू-बिजनेस बैठकों में छत्तीसगढ़ और चेन्नई के पर्यटन व्यवसायियों के बीच सार्थक संवाद हुआ, जिससे भविष्य में पर्यटक समूहों को छत्तीसगढ़ भ्रमण पर भेजने तथा कारोबारी साझेदारी बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत हुईं।

चेन्नई में आयोजित यह रोड शो छत्तीसगढ़ को दक्षिण भारत के प्रमुख पर्यटन बाजारों से जोड़ने की रणनीतिक पहल के रूप में सामने आया। रोड शो में छत्तीसगढ़ के पर्यटन उत्पादों, प्रमुख पर्यटन स्थलों और निवेश की संभावनाओं को चेन्नई के पर्यटन व्यवसायियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। BwB बैठकों के माध्यम से दोनों राज्यों के स्टेकहोल्डर्स को सीधे संवाद और संभावित व्यावसायिक सहयोग का अवसर मिला। कार्यक्रम में हुई चर्चा में पर्यटन व्यवसायियों की ओर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उनके संबोधन ने चेन्नई के पर्यटन व्यवसायियों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन से जोड़ने और राज्य की पर्यटन संभावनाओं के प्रति प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस अवसर पर पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन तथा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक सौमिल रंजन चौबे भी उपस्थित रहे। श्री चौबे ने छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों, पर्यटन उत्पादों तथा राज्य में उपलब्ध निवेश संभावनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

रोड शो का सबसे खास आकर्षण रहा—छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों और संभावनाओं को पहली बार तमिल भाषा में स्थानीय स्टेकहोल्डर्स के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। इस पहल ने चेन्नई के पर्यटन व्यवसायियों और स्थानीय पर्यटकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने अपने संबोधन में तमिल और अंग्रेजी भाषा में छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं विरासत संपदा की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने राज्य की पर्यटन संपदा को देश के प्रमुख पर्यटन बाजारों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। रोड शो में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की सहायक निदेशक एस. पद्मावती, फिक्की छत्तीसगढ़ टूरिज्म कमेटी के चेयरपर्सन एवं फिक्की छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष जसप्रीत सिंह भाटिया, फिक्की तमिलनाडु स्टेट काउंसिल के को-कन्वीनर श्रीहरन बालन तथा तमिलनाडु पर्यटन के निदेशक डॉ. वी.पी. जयसीलन सहित पर्यटन क्षेत्र के अनेक प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद रहे।

रोड शो की एक विशेष उपलब्धि यह भी रही कि छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ ट्रूस अधिकारी के.सी. देवासेनापति एवं एलेक्स पॉल मेनन, जो वर्तमान में चेन्नई में पदस्थ हैं, विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। दोनों अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ से अपने आत्मीय जुड़ाव और राज्य की पर्यटन संभावनाओं पर सारगर्भित विचार साझा किए। उनकी सहभागिता ने कार्यक्रम को एक अलग भावनात्मक आयाम प्रदान किया।

व्यापारिक साझेदारी के साथ दिखी सांस्कृतिक निकटता

चेन्नई रोड शो में छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के बीच पर्यटन क्षेत्र में व्यावसायिक साझेदारी के साथ-साथ आत्मीय जुड़ाव और सांस्कृतिक निकटता भी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। एक ही मंच पर छत्तीसगढ़ से जुड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ के पर्यटन कारोबारियों और चेन्नई के पर्यटन व्यवसायियों की सहभागिता ने आयोजन को विशेष बनाया।

15 सितम्बर तक मनाया जायेगा साक्षरता पखवाड़ा

दंतेवाड़ा। कलेक्टर एवं जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशानुसार तथा जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एम. भार्गव के मार्गदर्शन में जिले में 01 से 15 सितंबर 2026 तक साक्षरता पखवाड़ा एवं 08 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सभी के लिए शिक्षा पर केन्द्रित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत यह आयोजन किया जा रहा है। बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा सतत शिक्षा जैसे पांच प्रमुख घटकों पर आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

CAR DECOR
House Of Exclusive
Seat Cover,
Car Stereos Matting &
Sun Control Film &
Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower.
Opp. Indian Coffee House,
Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM
Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES
FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden)
Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles,
CPVC Pipes &
Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

नाबालिग से रेप, गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में युवक ने नाबालिग से करीब 3 साल तक रेप किया। जानकारी के मुताबिक, जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र से 27 अगस्त को कापू थाने में केस डायरी प्राप्त हुई। इसके आधार पर आरोपी दिनेश एक्का के खिलाफ धारा 64(2)(द्व) बीएनएस और धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। जांच के दौरान पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की वर्तमान उम्र 18 साल है। 24 अगस्त को उसने पेट में दर्द होने की बात कही। इसके बाद उसे सरकारी अस्पताल पत्थलगांव ले जाकर इलाज कराया गया। जांच में डॉक्टर ने उसके गर्भवती होने की जानकारी दी और बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर कर दिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी पिछले 3 साल से उसके गांव स्थित उसके मामा के घर आता-जाता था। इसी दौरान आरोपी ने प्रेम प्रसंग की बात कहकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार था। सूचना के आधार पर पुलिस ने गांव में दबिश देकर आरोपी दिनेश एक्का को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

करैत सांप के डसने से 13 वर्षीय छात्र की मौत

धमतरी। धमतरी जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच सर्पदंश की घटनाएं भी चिंता बढ़ा रही हैं। एक दर्दनाक हादसे में 13 वर्षीय कक्षा आठवीं के छात्र की करैत सांप के डसने से मौत हो गई। गिरिराज बया (13), पिता शिवशंकर, 1 सितंबर की रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद घर में जमीन पर सोया था। देर रात करीब 2 बजे उसने अपने पिता को जगाकर सांप के काटने की जानकारी दी। परिजनों ने तत्काल कमरे की लाइट जलाकर देखा तो बिस्तर के पास करैत सांप मौजूद था। परिजन बिना देरी किए उसे इलाज के लिए कुरूद अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि, उपचार के दौरान उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका और बुधवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया। पंचनामा कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है, वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल है।

दुर्ग पुलिस ने ली डीजे व पंडाल संचालकों की बैठक, त्योहारों में व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश

पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर-6 में हुई बैठक में पहुंचे 50 से अधिक डीजे व पंडाल संचालक

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। त्योहार सीजन के दौरान सार्वजनिक आयोजनों में डीजे, साउंड सिस्टम एवं पंडालों के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए दुर्ग पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जिले के संबंधित संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में डीजे संचालक संघ के पदाधिकारी सहित जिले के 50 से अधिक संचालक उपस्थित रहे। बैठक में आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए दुर्ग पुलिस एवं प्रशासन द्वारा डीजे, साउंड सिस्टम, पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों को कानून-व्यवस्था, यातायात, ध्वनि प्रदूषण एवं सुरक्षा मानकों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण WPPIL(C)-88/2023, दिनांक 20.11.2023 में पारित निर्देशों तथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 एवं The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 में निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संचालकों को निर्देशित किया गया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर शोभराज अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक हर्षित मेहर, नगर पुलिस अधीक्षक छावनी प्रशांत पैकरा, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निशांत पाठक सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

संचालकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि आगामी त्योहारों के दौरान डीजे एवं साउंड सिस्टम का संचालन निर्धारित कानूनी प्रावधानों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए।

दुर्ग पुलिस सभी डीजे, साउंड सिस्टम, पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों से अपील करती है कि आगामी त्योहारों के दौरान निर्धारित नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही आयोजन करें। ध्वनि प्रदूषण, यातायात अवरोध एवं सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन न करें। नियमों का पालन कर शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित त्योहार आयोजन में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें।

डीजे एवं साउंड सिस्टम संचालकों के लिए निर्देश

- सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि स्तर से 10 डीबी(ए) से अधिक अथवा 75 डीबी(ए) से अधिक नहीं किया जाए; दोनों में जो भी कम हो, वही सीमा लागू होगी।
- रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाद्य यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- एनजीटी एवं शासन द्वारा निर्धारित ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण मानकों, कोलाहल अधिनियम तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।
- वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र अथवा वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाए।
- ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ ध्वनि मापक यंत्र उपलब्ध रखा जाए तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही ध्वनि का संचालन किया जाए।
- शासकीय एवं अशासकीय अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय एवं शासकीय कार्यालयों की 100 मीटर सीमा को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन ऑफसाइलेंस) के रूप में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार माना जाए।

पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों के लिए निर्देश

- पंडाल निर्धारित व्हाइट मार्किंग के पीछे ही लगाए जाएं तथा किसी भी स्थिति में मुख्य मार्ग, आवागमन अथवा आपातकालीन रास्ते को अवरुद्ध नहीं किया जाए।
- पंडाल लगाने से पूर्व नगर निगम एवं संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति एवं अनापत्ति प्राप्त की जाए।
- पंडाल में फायर सेफ्टी एवं इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
- पंडाल की क्षमता एवं संरचना का आवश्यक सुरक्षा ऑडिट कराकर ही आयोजन किया जाए, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को कम किया जा सके।

पिता की डांट से नाराज होकर घर से निकला 13 वर्षीय बच्चा, फंदे से लटका मिला शव

श्रीकंचनपथ समाचार

एमसीबी। मरवाही जिले में पेंड्रा थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में 13 वर्षीय बच्चे की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बच्चा मंगलवार शाम पिता की डांट के बाद घर से निकल गया था। अगले दिन खेत की ओर गए ग्रामीणों ने कच्ची सड़क से कुछ दूरी पर पेड़ के पास बच्चे का शव देखा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

मृतक की पहचान समर सिंह पोरते (13 वर्ष) के रूप में हुई है। वह अमरपुर गांव का रहने वाला था। उसके पिता बुधराम सिंह पोरते ने किसी बात को लेकर उसे डांटा था। इसके बाद समर नाराज होकर बिना किसी को बताए घर से निकल गया। कुछ समय बीतने के बाद जब वह वापस नहीं लौटा तो परिवार की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने आसपास के इलाकों और गांव में उसकी तलाश शुरू की, लेकिन देर रात तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी। बुधवार को कुछ ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कच्ची सड़क से कुछ अंदर पेड़ के पास बच्चे को फंदे पर लटका देखा। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी। घटना की जानकारी फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बच्चे की मौत से परिवार में मातम छा गया। पेंड्रा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती तौर पर पिता की डांट से नाराज होकर बच्चे के घर से निकलने की जानकारी सामने आई है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

सुनसान कमरे में मिला युवक का शव, तीन दिनों से लापता था, जांच में जुटी पुलिस

श्रीकंचनपथ समाचार

कोरबा। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र के आंची दादर में गुरुवार को एक सुनसान कमरे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अभिनय रजक पिता शंकर रजक के रूप में हुई है। शव मिलने की खबर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने कमरे में शव पड़ा देखा तो इसकी सूचना तुरंत कटघोरा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई शुरू की।

कटघोरा थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है। सुनसान कमरे में शव मिलने के कारण मामला संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाए हैं और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

नशे का आदी होने की भी जानकारी

स्थानीय लोगों के अनुसार, अभिनय शराब पीने का आदी था और अक्सर नशे में रहता था। आशंका जताई जा रही है कि नशे की हालत में वह कमरे में गया होगा, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि, पुलिस ने अभी किसी संभावना की पुष्टि नहीं की है।

फिलहाल पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। युवक आखिरी बार कब और किसके साथ देखा गया था, वह कमरे तक कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

फोटो वायरल करने की धमकी पर भड़का विवाद दोस्त की पिटाई से 15 दिन बाद बुजुर्ग की मौत

श्रीकंचनपथ समाचार

कोरबा। कोरबा जिले में घर की दहलीज पर बैठकर दोस्तों के साथ शराब पीने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ी। शराब के नशे में उसके ही दोस्त ने डंडे से हमला करने के बाद हाथ-मुक्कों और लात-घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग ने करीब 15 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद दम तोड़ दिया। मामला जटगा पुलिस चौकी क्षेत्र के महगवां डांड जटगा गांव का है।

मृतक की पहचान 64 वर्षीय प्रसाद सिंह नेटी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, घटना 18 अगस्त की रात करीब 9 बजे की है। उस समय पत्नी मायके गई हुई थी और प्रसाद घर पर अकेला था। इसी दौरान उसके दोस्त हीरासिंह नेटी और समारू उर्फ बबलू नेटी वहां पहुंचे। तीनों घर की दहलीज पर बैठकर मछली के साथ महुआ शराब पी रहे थे। इसी बीच गांव का युवक राहुल नेटी वहां से गुजरा। उसने तीनों की शराब पीते हुए तस्वीर मोबाइल से खींच ली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात कहते हुए वहां से चला गया। उसने प्रसाद पर ही राहुल को बुलाकर फोटो खिंचवाने का आरोप लगाया और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर समारू ने घर में रखे डंडे से प्रसाद पर हमला कर दिया। आरोप है कि उसने डंडा टूटने तक प्रसाद को पीटा और इसके बाद जमीन पर पटककर लात-मुक्कों से भी मारपीट की। इसके बाद हीरासिंह वहां से भागकर अपने घर पहुंचा और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी।

अगले दिन ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिलने पर उसे पौड़ी उपरोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। करीब 15 दिनों तक अस्पताल में इलाज चलने के बाद मंगलवार शाम प्रसाद सिंह की मौत हो गई। अस्पताल पुलिस ने मेमो के आधार पर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में पुलिस आरोपी समारू उर्फ बबलू नेटी की तलाश कर रही है।

सड़क हादसा नहीं, ट्रक विवाद में हत्या!

दोस्त ने साथी संग मिलकर युवक को पीटा, शव कार के नीचे डाल रची साजिश

श्रीकंचनपथ समाचार

जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसा मानकर जांचे जा रहे एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि युवक की मौत दुर्घटना में नहीं, बल्कि कथित तौर पर मारपीट के दौरान हुई थी। पुलिस के मुताबिक, ट्रक के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में दोस्त ने अपने साथी के साथ मिलकर युवक की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद वारदात को सड़क हादसा दिखाने के लिए शव को कार के नीचे डाल दिया गया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है।

पुलिस के अनुसार, 24 जून 2026 को सोनादुला-सांकर भारतमाला रोड पर वाहन क्रमांक सीजी 10 बीपी 9060 से जुड़ी घटना में 26 वर्षीय अरविंद सिंह लोधी, निवासी सकरी, बिलासपुर

की मौत हुई थी। शुरुआती जांच में मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हुआ था। इसी आधार पर पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ धारा 106(1) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में ट्रक के लेन-देन को लेकर मृतक और आरोपी के बीच पुराने विवाद की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन शराब पीने के दौरान दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। आरोप है कि हेमंत सिंह ठाकुर ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर अरविंद की लात-घूंसों से जमकर पिटाई की। इसी दौरान अरविंद की मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने घटना को दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को कार के नीचे रख दिया।

जांच में हत्या के तथ्य सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में धारा 103(1) और 3(5) बीएनएस जोड़ी है। वहीं, पहले दर्ज धारा 106(1) बीएनएस को हटा दिया गया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपी हेमंत सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं, वारदात में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है।

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

पक्षकार- छ.ग. रेरा, शास्त्री चौक
जिला-रायपुर (छ.ग.) ..... आवेदक

बनाम

प्रमोटर- श्री बालाजी बिल्डर्स,
(श्री जुगल किशोर तिवारी),पता-शिव अर्पण बिल्डिंग, दक्षिण गंगोत्री,
सुपेला भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
प्राधिकरण का प्रकरण क्रमांक-SM-URP-2025-03213)
(खसरा नंबर-617/17, प्रियंका नगर),
(खसरा नंबर-95/43, आदर्श नगर) ..... अनावेदक

सूचना तामिली पक्षकार- श्री बालाजी बिल्डर्स, (श्री जुगल किशोर तिवारी), पता-शिव अर्पण बिल्डिंग, दक्षिण गंगोत्री, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को प्रकरण में सुनवाई हेतु उपस्थिति के लिए सूचना तामिली हेतु।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तरवादी/ प्रमोटर-श्री बालाजी बिल्डर्स, (श्री जुगल किशोर तिवारी), पता-शिव अर्पण बिल्डिंग, दक्षिण गंगोत्री, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) के विरूद्ध छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर के समक्ष अधिनियम की धारा-03 के अधीन संधारित क्रमशः प्रकरण क्रमांक-SM-URP-2025-03213 है। उत्तरवादी को दस्तावेज में उल्लेखित पते पर सूचना पत्र (नोटिस) प्रेषित किया गया था, जो कि अदम तामिल प्राप्त हुए है।

अतएव उक्त परिवाद में आगामी सुनवाई तिथि 16/09/2026 को प्रातः 11.00 बजे नियत किया गया है। आप उक्त तिथि में नियत समय पर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष स्वयं अथवा विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए उत्तरवादी स्वतः जवाबदार होंगे।

आज दिनांक 25/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं प्राधिकरण के पदमुद्रा से जारी किया गया।

(मान. प्राधिकरण द्वारा आदेशित)
मुहर
S-48933/3

sd/-
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रिसाली

(सम्पत्तिकर विभाग)

स.क.वि./2026-27/ 361 दिनांक 31/8/26

// स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना //

इस इंश्तहार द्वारा हित रखने वाले हितग्राही हो एहद द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 में स्वत्याधिकार के अंतरण के संबंध में निम्नलिखित हस्तांतरिती के नाम से जिसका की नगर पालिक निगम रिसाली के सम्पत्तिकर अभिलेख में हस्तांतरणकर्ता के स्थान पर नाम दर्ज किया जाना है। यदि किसी को इस संबंध में कोइ आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है बाद में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	हस्तांतरणकर्ता का नाम	हस्तांतरिती का नाम	हस्तां. का स्वरूप	सम्पत्ति की स्थिति
1.	स्व. जी. एन. मिश्रा/पिता-स्व. श्री शिवध्यान मिश्रा, पता-म.नं. 10 स्ट्रीट नं. 4ए, मैत्री नगर रिसाली, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	(1) विद्यावाती देवी/पति-स्व. जी. एन. मिश्रा पता-म.नं. 10 स्ट्रीट नं. 4ए, मैत्री नगर रिसाली, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) (2) अजित कुमार मिश्रा/पिता- स्व. जी. एन मिश्रा, पता-164 बी, रूआवांधा सेक्टर (3) संजय कुमार मिश्रा/पिता- स्व. जी. एन मिश्रा पता-164 बी, रूआवांधा सेक्टर (4) विजय कुमार मिश्रा/पिता- स्व. जी. एन. मिश्रा, पता-एस.एस./401 सुभाष नगर दन्तेवाड़ा (5) आशा पाण्डेय/पिता- स्व. जी. एन. मिश्रा, पता-32/5ए, मैत्री नगर रिसाली (6) अम्बे उपाध्याय/पिता- स्व. जी. एन. मिश्रा, पता-प्लाट नं. 2, स्ट्रीट 20/बी, प्रगति नगर रिसाली (7) सिद्धि दविवेदी/पिता- स्व. जी. एन. मिश्रा, पता-215बी रिसाली सेक्टर भिलाई	वारिसाना हकत्याग	म.नं. 10 स्ट्रीट नं. 4ए, मैत्री नगर रिसाली, खसरा नं. 189/74, कुल रकबा 2400 वर्गफीट है।
2	स्व. श्री महेश कुमार दुबे/पिता-स्व. निश्रीलाल दुबे, पता-क्वा. नं. 24/बी, सड़क नं. एन.पी.ए., सेक्टर 5, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती मंजू दुबे/पति-स्व. महेश कुमार दुबे, पता-क्वा. नं. 24/वी, सड़क नं. एन.पी.ए., सेक्टर 5, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	वारिसाना हकत्याग	लक्ष्मी नगर रिसाली, वार्ड नं. 29 अन्दर भाग, प.ह.नं. 19, खसरा नं. 1078/8, कुल रकबा 2400 वर्गफीट है।
3	(1) नवीन्द्र लाल/पिता स्व. किशोरी लाल स्वर्णकार (2) मुरली प्रसाद/पिता-स्व. किशोरी लाल स्वर्णकार, पता-सदर बाजार दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्री गिरीश चौरसिया/पिता स्व. यू. आर. चौरसिया, पता-क्वा. नं. 198/वी, वी. एस. पी. रूआवांधा सेक्टर, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	विक्रीनामा	सरस्वती कुंज पश्चिम रिसाली, खसरा नं. 672/24, कुल रकबा 2000 वर्गफीट है।
4	खुर्शीद अहमद/पिता स्व. मोहम्मद उमर अंसारी, पता-181/16, स्ट्रीट नं. 20/सी, प्रगति नगर रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	प्रवीण कुमार जैन/पिता श्री निर्मल जैन, पता-प्लाट नं. 123, स्ट्रीट नं. 20, शिव मंदिर के पास, प्रगति नगर रिसाली, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	विक्रीनामा	रिसाली वार्ड नं. 22, मैत्री कुंज रिसाली वार्ड, प.ह.नं. 49, ख.नं. 181/16, कुल रकबा 1500 वर्गफीट है।
5	(1) तारा देवी माहापात्रो/पति स्व. जे. टी. माली, पता सूरज बेकरी के पास, इस्पात नगर, रिसाली भिलाई छ.ग. (2) सुषमा माहापात्रो उर्फ शीतल दीवकर/पिता स्व. जे. टी. माली, पता-इंचार्ज आफ सांई ट्रेनिंग सेंटर, स्पोट्स काम्प्लेक्स, कुर्तीपोण्डा, गोवा	(1) कृष्णचंद माहापात्रो/पिता स्व. जे.टी. माली (2) रमेश माहापात्रो/पिता स्व. जे.टी. माली, दोनों निवासी- सूरज बेकरी के पास, इस्पात नगर, रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	हकत्याग	रिसाली, वार्ड नं. 60, रिसाली बस्ती वार्ड अंतर्गत इस्पात नगर अंदर भाग प.ह.नं. 14/19, ख. नं. 1022/8, कुल रकबा 1600 वर्गफीट में से हकत्याग का रकबा 800 वर्गफीट है।

उक्त संबंध में अंतरण के पूर्व इश्तहार जारी किया जाता है, जिसमें संबंधिती द्वारा प्रकाशन एवं नामांतरण शुल्क जमा किया गया है। अतः समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत।

जनसंपर्क अधिकारी
न.प.नि. रिसाली

सहायक राजस्व अधिकारी
नगर पालिक निगम रिसाली

अपार्टमेंट के पास मिला मानव भ्रूण, जांच में जुटी पुलिस

कोरबा। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मानव भ्रूण मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। भद्रापारा मुख्य मार्ग पर स्थित श्री अपार्टमेंट के समीप एक भ्रूण पड़ा मिला, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। भ्रूण मिलने की खबर तेजी से पूरे इलाके में फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि भ्रूण मृत अवस्था में मिला है। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। एक बार फिर समाज में कन्या भ्रूण हत्या और असुरक्षित प्रसव जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

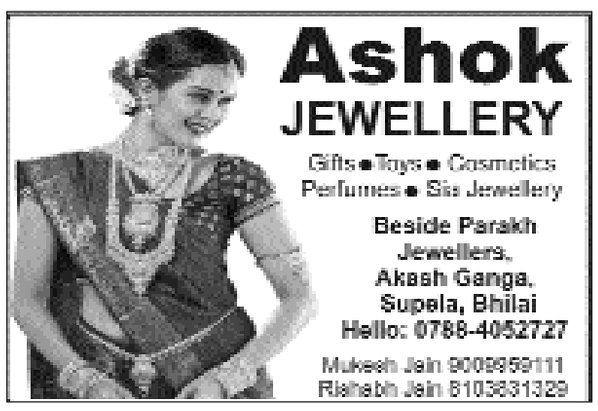

खास खबर

जल संरक्षण जागरूकता बढ़ाने जल अर्पण दिवस का आयोजन

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण होने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायतों को औपचारिक रूप से योजना हस्तांतरित करने के उद्देश्य से जल अर्पण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विकासखंड गौरेला के ग्राम बेदखोदरा में जल अर्पण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बेदखोदरा के सरपंच को जल अर्पण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इन आयोजनों के माध्यम से ग्रामीणों में 'जल संरक्षण, जल संवर्धन और जल का विवेकपूर्ण उपयोग' के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के साथ ही हर घर तक सुरक्षित एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में किए गए प्रयासों को जनभागीदारी से और मजबूत किया जा रहा है।

करेले की खेती से बढ़ी किसान नारायण प्रसाद वर्मा की आय

महासमुन्द। जिले के विकासखण्ड बागबाहरा अंतर्गत ग्राम टेंगराही के कृषक नारायण प्रसाद वर्मा ने पारंपरिक खेती के साथ उद्यानिकी फसलों को अपनाकर अपनी आय में अच्छी वृद्धि की है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के सहयोग तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग से वे आज क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन रहे हैं। श्री वर्मा के पास कुल 1.06 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसमें वे वर्षभर अलग-अलग उद्यानिकी फसलों की खेती करते हैं। ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग एवं आधुनिक कृषि यंत्रों जैसी नवीन तकनीकों फसल उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार हुआ है। प्रति एकड़ करेला की खेती से लगभग 12 टन उत्पादन प्राप्त किया हैं। सभी खर्च को काटकर 1 लाख 7 हजार रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ।

बस्तर संभाग में शिक्षक दिवस पर सजेगा सम्मान का मंच

जगदलपुर। 'मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना अंतर्गत 2026' का संभागीय समारोह जगदलपुर स्थित श्यामाप्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। संभाग के प्रत्येक जिले से एक-एक उत्कृष्ट प्राचार्य का चयन किया गया है, जिसमें बस्तर से श्रीमती मनोरमा बौद्ध, बीजापुर से राधेश्याम कुलदीप, दंतेवाड़ा से शैफाली भदौरिया, कांकेर से टिकेश्वर सिंह ठाकुर, कोण्डागांव से महावीर जायसवाल, नारायणपुर से गणेश प्रसाद दुग्गा और सुकमा से सहदेव सिंह शामिल हैं। इसके अतिरिक्त संभाग के 7 जिलों के सभी 32 विकासखंडों से जमीनी स्तर पर शिक्षा की अलख जगा रहे 32 प्राथमिक शाला और 32 माध्यमिक शाला के प्रधान पाठकों, यानी कुल 64 संस्था प्रमुखों को उनके अनुकरणीय शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चुना गया है।

ग्राम पंचायत परासी के पूर्व सचिव मरावी निलंबित

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जिला पंचायत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत परासी, जनपद पंचायत मरवाही के तत्कालीन पंचायत सचिव ओंकार सिंह मरावी को शासकीय राशि के समुचित उपयोग एवं वसूली के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना तथा कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। परासी में जिला खनिज न्यास मद से पूर्व माध्यमिक शाला भवन निर्माण के लिए 7 लाख 96 हजार रुपये जारी की गई थी। आहरण के बाद कार्य का अपेक्षित निष्पादन नहीं किया गया।

लीलाराम साहू ने 'निरंजन भाटा' को दिलाई राष्ट्रीय पहचान

धमतरी। कुरूद विकासखंड के ग्राम घुमा, दर्रा निवासी स्व. लीलाराम साहू द्वारा वर्षों से संरक्षित पारंपरिक एवं विशिष्ट बैंगन किस्म 'निरंजन भाटा' को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान किया गया। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कलेक्टर कार्यालय में स्व. श्री साहू के पुत्र अजय शंकर साहू को उनके पिता के कृषि क्षेत्र में योगदान, पारंपरिक कृषि ज्ञान के संरक्षण तथा स्थानीय जैव-विविधता को सहेजने के लिए सम्मानित किया। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि पारंपरिक फसल किस्में केवल कृषि विरासत नहीं, बल्कि पीढ़ियों से संचित ज्ञान, अनुभव और स्थानीय जैव-विविधता की अमूल्य धरोहर हैं। 'निरंजन भाटा' जैसी स्थानीय किस्म का संरक्षण और उसका राष्ट्रीय स्तर पर पंजीयन धमतरी जिले के लिए गौरव की बात है।

'जल संचय जन भागीदारी' का तीसरा चरण

28 लाख से अधिक जल संरचनाओं के साथ बारिश की हर बूंद को सहेजने में छत्तीसगढ़ बना नम्बर-1

- प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया छत्तीसगढ़ का जनभागीदारी आधारित जल संरक्षण मॉडल
- खेत का 5 प्रतिशत हिस्सा जल संरक्षण के लिए देने की किसानों की अनूठी पहल बनी मिसाल
- सूरजपुर, महासमुंद, बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा और कबीरधाम देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। बारिश की हर बूंद को सहेजने और उसे धरती के भीतर पहुंचाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने देश के सामने जनभागीदारी का प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है। जल शक्ति मंत्रालय के 'जल संचय जन भागीदारी' अभियान के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य के पांच जिले भी जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के शीर्ष 10 जिलों में स्थान बनाने में सफल रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे नवाचारों और जनभागीदारी आधारित प्रयासों की जानकारी राष्ट्रीय मंच पर साझा की। सम्मेलन के 'कैच द रेन' सत्र में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य में वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण तथा पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण को केवल शासकीय योजनाओं और जल संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं रखा है। किसानों, ग्राम पंचायतों, जल सखियों, जल मित्रों और स्थानीय समुदायों को इससे जोड़कर इसे व्यापक जनअभियान का स्वरूप दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और अपने गृहग्राम बगिया में हल चलाकर खेती कर चुके हैं। इसलिए खेती और ग्रामीण जीवन में पानी का महत्व उन्होंने बहुत करीब से देखा और समझा है। किसान के लिए पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि उसकी फसल, परिवार, आजीविका और भविष्य से जुड़ा विषय है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण की योजनाओं के केंद्र में किसान और गांव को रखा गया है।

उन्होंने कहा कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग चार प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला छत्तीसगढ़ 'जल संचय जन भागीदारी' अभियान में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। यह उपलब्धि केवल जल संरचनाओं की संख्या की नहीं, बल्कि जल संरक्षण के प्रति प्रदेश में विकसित हो रही सामूहिक चेतना और जनभागीदारी की भी उपलब्धि है।

सूरजपुर, कबीरधाम सहित छत्तीसगढ़ के पांच जिले देश के टॉप-10 में

राज्य स्तर की उपलब्धि के साथ ही छत्तीसगढ़ के जिलों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। जल संरक्षण के क्षेत्र में सूरजपुर, महासमुंद, बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा और कबीरधाम देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुए हैं।

इन जिलों में जल संरक्षण को स्थानीय समुदायों से जोड़ते हुए गांव और पंचायत स्तर पर वर्षा जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण के कार्य किए गए हैं। स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप जल संरचनाओं के निर्माण के साथ लोगों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि बताती है कि जब शासन की योजनाओं के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी जुड़ती है, तो जल संरक्षण जैसे बड़े लक्ष्य को भी जनांदोलन का रूप दिया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में पानी की कमी वाले ब्लॉक थे 26, अब रह गए 19

राज्य में किए जा रहे जल संरक्षण प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पानी की कमी वाले ब्लॉकों की संख्या 26 से घटकर 19 रह गई है। साथ ही पांच क्रिटिकल ब्लॉकों के भी सामान्य श्रेणी में आने का अनुमान है।

भू-जल की स्थिति में सुधार के लिए राज्य में जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के साथ पुराने जल स्रोतों के संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, जल संरचनाओं की मैपिंग और स्थानीय स्तर पर नियमित निगरानी पर जोर दिया जा रहा है।

जल संरक्षण से खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

देश में 31 मई 2027 तक दो करोड़ नई जल संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में छत्तीसगढ़ का जनभागीदारी मॉडल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

बारिश का पानी खेतों और गांवों में रोकने तथा उसे जमीन में पहुंचाने से भू-जल स्तर में सुधार के साथ सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ सकती है। इसका सीधा लाभ खेती को मिल सकता है और किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

जल उपलब्धता बेहतर होने से कृषि और उससे जुड़े आजीविका के अवसरों को भी मजबूती मिल सकती है। गांवों में पेयजल स्रोतों की स्थिति बेहतर होने से परिवारों, विशेषकर महिलाओं को पानी जुटाने में लगने वाले समय और श्रम में भी कमी आ सकती है।

छत्तीसगढ़ का यह मॉडल बताता है कि जल संरक्षण केवल संरचनाओं के निर्माण का विषय नहीं है। यह सरकार, किसान, पंचायत और समाज की साझा जिम्मेदारी है। खेत का एक छोटा-सा हिस्सा पानी के लिए छोड़ने से शुरू हुई पहल भविष्य के लिए जल सुरक्षित करने के बड़े अभियान का आधार बन सकती है।

शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

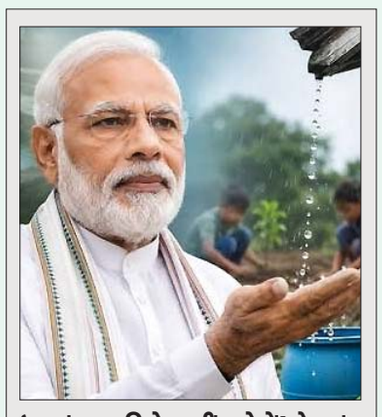

'जहां जल गिरे, वहीं सहेजें' के मंत्र को जमीन पर उतार रहा छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'कैच द रेन - जहां जल गिरे, वहीं सहेजें' के संदेश को छत्तीसगढ़ ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप धरातल पर उतारा है। प्रदेश की भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों में वहां की आवश्यकता और जल उपलब्धता के अनुसार जल संचयन तथा भू-जल पुनर्भरण की संरचनाएं विकसित की जा रही हैं।

राज्य का प्रयास है कि बारिश का अधिकतम पानी गांव और खेत की सीमा के भीतर ही रोका जाए। इससे न केवल भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सिंचाई, पेयजल और अन्य स्थानीय जरूरतों के लिए जल उपलब्धता को भी बेहतर बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ जल संरक्षण के अपने अनुभवों, नवाचारों और सफल मॉडलों को देश के अन्य राज्यों के साथ साझा करने के लिए तैयार है।

कोरिया से निकला '5 प्रतिशत मॉडल', किसान स्वयं दे रहे जमीन

मुख्यमंत्री श्री साय ने सम्मेलन में कोरिया जिले से शुरू हुए '5 प्रतिशत मॉडल' का विशेष उल्लेख किया। यह मॉडल जल संरक्षण में किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी का अभिनव उदाहरण है।

इस पहल के अंतर्गत किसान अपनी कृषि भूमि का लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा भू-जल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए स्वेच्छा से उपलब्ध करा रहे हैं। इस हिस्से में ऐसी जल संरचनाएं विकसित की जा रही हैं, जिनमें बारिश का पानी खेत से बहकर बाहर जाने के बजाय वहीं एकत्र हो और धीरे-धीरे जमीन के भीतर समाहित हो सके।

इस मॉडल की विशेषता यह है कि इसमें किसान जल संरक्षण के केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार हैं। किसान अपनी भूमि उपलब्ध करा रहे हैं, पंचायतें और स्थानीय समुदाय सहयोग कर रहे हैं तथा विभिन्न विभागों और योजनाओं के समन्वय से जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

जल संरचनाओं की जियो-टैगिंग, नियमित मॉनिटरिंग और प्रगति की समीक्षा को भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। जल सखी, जल मित्र, किसान और पंचायत प्रतिनिधि गांवों में जल संरक्षण की इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं।

खेत में ही वर्षा जल को रोकने से भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलने के साथ सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होने की संभावना है। लंबे समय में इससे खेती की वर्षा पर निर्भरता कम करने और जल सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

प्रत्येक राज्य बनाए अपना अपना 'कैच द रेन' प्लान : साय

मुख्यमंत्री श्री साय ने सम्मेलन में देशभर में जल संरक्षण अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य अपनी भौगोलिक परिस्थितियों, वर्षा के स्वरूप, भू-जल स्थिति और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अलग 'कैच द रेन प्लान' तैयार करे। इससे जल संरक्षण के लिए राज्यवार स्पष्ट लक्ष्य और रणनीति निर्धारित की जा सकेगी। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 'स्टेट वाटर अवार्ड्स' प्रारंभ करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने BISAG-N के माध्यम से जल संरचनाओं की मैपिंग की व्यवस्था को और मजबूत करने तथा अभियान की प्रगति की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक तीन महीने में समीक्षा करने का भी सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक, नियमित मॉनिटरिंग और जनभागीदारी - इन तीनों के समन्वय से जल संरक्षण के प्रयासों को अधिक परिणाममूलक बनाया जा सकता है।

जेएसजेबी 3.0 में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल

जल शक्ति मंत्रालय के 'जल संचय जन भागीदारी' अभियान के तीनों चरणों में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। पहले दो चरणों में देश में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद तीसरे चरण में राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

'जल संचय जन भागीदारी' अभियान के प्रथम चरण जेएसजेबी 1.0 में छत्तीसगढ़ में 4 लाख 5 हजार 561 जल संरचनाएं बनाई गईं। इस चरण में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर रहा। दूसरे चरण जेएसजेबी 2.0 में प्रदेश में 24 लाख 7 हजार 456 जल संरचनाएं दर्ज की गईं। इनमें से 23 लाख 7 हजार 768 जल संरचनाओं का कार्य पूरा हो चुका है। इस चरण में भी छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया।

अब तीसरे चरण जेएसजेबी 3.0 में छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस चरण में प्रदेश में 79 हजार 775 जल संरचनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से 77 हजार 719 जल संरचनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार अभियान के अलग-अलग चरणों में छत्तीसगढ़ ने बड़े पैमाने पर जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण की संरचनाओं को विकसित और दर्ज किया है। इन प्रयासों का मूल उद्देश्य बारिश के पानी को बहकर बाहर जाने से रोकना, स्थानीय स्तर पर उसका संचयन करना और अधिक से अधिक पानी को जमीन के भीतर पहुंचाना है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950